CMYK CMYK

वित्त वर्ष 2024-25 पूरा होने से पहले सरकारी ई-मार्केटप्लेस ने 5 लाख करोड़ का जीएमवी पार किया

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

लोक शक्ति

RNI Regn. No.7789/1964

थोक महंगाई फरवरी में बढ़कर 2.38% पर पहुंची

वर्ष-61 › अंक - 80 रायपुर शुक्रवार 21 मार्च 2025 विक्रम संवत 2081 पृष्ठ 8 › मूल्य : 2 रू डाक पंजीयन : C.G./RYP DN/71/2023-25

अगले साल 31 मार्च से पहले देश नक्सलमुक्त होने वाला है : अमित शाह

नक्सलियों के खिलाफ मोदी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है

एजेंसी

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार नक्सलियों के विरुद्ध रुथलेस अप्रोच के साथ आगे बढ़ रही है।

आज छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों द्वारा दो अलग-अलग अभियानों में 22 नक्सलियों के मारे जाने के बाद प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में श्री अमित शाह ने कहाकि 'नक्सलमुक्त भारत अभियान' की दिशा में आज हमारे जवानों ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और कांकेर में हमारे सुरक्षा बलों के 2 अलग-अलग ऑपरेशन्स में 22 नक्सली मारे गए। मोदी सरकार नक्सलियों के विरुद्ध रुथलेस अप्रोच से आगे बढ़ रही है और समर्पण से लेकर समावेशन की तमाम सुविधाओं के बावजूद जो नक्सली आत्मसमर्पण नहीं कर रहे, उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। अगले साल 31 मार्च से पहले देश नक्सलमुक्त होने वाला है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व और केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में नक्सलवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति के चलते वर्ष 2025 में अब तक 90 नक्सली मारे जा चुके हैं, 104 को गिरफ्तार किया गया है और 164 ने आत्मसमर्पण किया है। वर्ष 2024 में 290 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज़ किया गया था, 1090 को गिरफ्तार किया गया और 881 ने आत्मसमर्पण किया था। अभी तक कुल 15 शीर्ष नक्सली नेताओं को न्यूट्रलाइज़ किया जा चुका है।

वर्ष 2004 से 2014 के बीच नक्सली हिंसा की कुल 16,463 घटनाएं हुई थीं, जबकि मोदी सरकार के कार्यकाल में 2014 से 2024 के बीच हिंसक घटनाओं की संख्या 53 प्रतिशत घटकर 7,744 रह गई हैं। इसी प्रकार, सुरक्षाबलों की मृत्यु की संख्या 1851 से 73 प्रतिशत घटकर 509 रह गई और नागरिकों की मृत्यु की संख्या 70 प्रतिशत की कमी के साथ 4766 से 1495 रह गई है।

वर्ष 2014 तक कुल 66 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन थे जबकि मोदी सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल में इनकी संख्या बढ़कर 612 हो गई है। इसी प्रकार, 2014 में देश में 126 ज़िले नक्सलप्रभावित थे, लेकिन 2024 में सबसे अधिक प्रभावित ज़िलों की संख्या घटकर मात्र 12 रह गई है। पिछले 5 वर्षों में कुल 302 नए सुरक्षा कैंप और 68 नाइट लैंडिंग हेलीपैड्स बनाए गए हैं।

बीजापुर में 30 नक्सली ढेर, एक जवान शहीद

पुलिस के अनुसार, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिलों की सीमा से सटे जंगलों में सुबह करीब 7 बजे मुठभेड़ हुई. सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम गंगालूर थाना क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान पर थी, तभी नक्सलियों से आमना-सामना हो गया. इसमें 18 नक्सलियों को मार गिराया गया और भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए. हालांकि, इस मुठभेड़ में डीआरजी के एक जवान ने भी शहादत दी.

पीएम मोदी के दौरे से पहले बिहार पहुंचेंगे अमित शाह

संवाददाता।

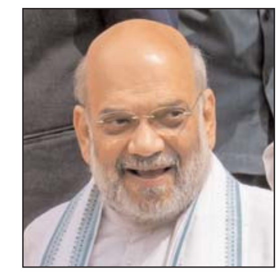

शाह के संभावित दौरे ने राज्य की राजनीति को गरमा दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन सहयोगियों ने एनडीए उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया था। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में भी यही रणनीति अपनाई गई, जिसने तीन दशक के अंतराल के बाद राष्ट्रीय राजधानी में भगवा पार्टी की सत्ता में वापसी का मार्ग प्रशस्त किया।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा करने के लिए 29 मार्च को बिहार का दौरा कर सकते हैं। शाह अगले दिन पार्टी के राज्य मुख्यालय में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर सकते हैं। भाजपा के सूत्रों ने बताया कि शाह आगामी विधानसभा चुनावों में सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए उम्मीदवारों के लिए संयुक्त चुनाव प्रचार अभियान के लिए गठबंधन के शीर्ष सहयोगियों के साथ भी बातचीत करेंगे।

शाह के संभावित दौरे ने राज्य की राजनीति को गरमा दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन सहयोगियों ने एनडीए उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया था। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में भी यही रणनीति अपनाई गई, जिसने तीन दशक के अंतराल के बाद राष्ट्रीय राजधानी में भगवा पार्टी की सत्ता में वापसी का मार्ग प्रशस्त किया। भाजपा की राज्य कोर कमेटी के सदस्य और वरिष्ठ भाजपा नेता ने बताया, ÷स्टार प्रचारक सभी एनडीए उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों। वे सभी एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगे।÷

आदित्य ठाकरे पर FIR की मांग लेकर HC पहुंचे दिशा सालियान के पिता

एजेंसी। सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है. दिशा के पिता सतीश सालियान अब बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे हैं जहां उन्होंने मांग की है कि उनकी बेटी की मौत की जांच नए सिरे से की जाए. उन्होंने शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की है. मुताबिक दिशा सालियान के पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी के साथ पहले रेप किया गया था और फिर उसका मर्डर कर दिया गया. उन्होंने दावा किया कि कुछ प्रभावशाली लोगों को बचाने के लिए इस मामले में राजनीतिक रूप से साजिश की गई है. सतीश सालियान ने हाईकोर्ट से अपील की है कि उनकी बेटी की मौत की इन्वेस्टीगेशन सीबीआई को ट्रांसफर कर दी जाए।

नागपुर में कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील के बाद दूध-सब्जी खरीदने निकले लोग

संवाददाता।

नागपुर दंगे के 72 घंटे बाद कर्फ्यू में ढील दी गई है। नागपुर के कुछ थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील दी गई है। लकड़गंज, पाचपावली, शांतिनगर, सक्करदरा, इमामवाड़ा और यशोधरानगर में आज दोपहर 2 बजे से शाम चार बजे के बीच कर्फ्यू में ढील दी गई। वहीं पुलिस कमिश्नर के ऑर्डर के बाद आज नंदनवन और कपिलनगर में कर्फ्यू पूरी तरह हटा दिया गया है। कर्फ्यू में ढील देने से पहले पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों ने संवेदनशील इलाकों को लेकर समीक्षा बैठक की उसके बाद ये फैसला लिया। बता दें कि दंगे के बाद नागपुर पुलिस ने शहर के 11 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया था।

जरूरत का सामान लेने के लिए कर्फ्यू में ढील

नागपुर में जैसे ही लोगों को पता लगा कि कर्फ्यू में 2 घंटे की ढिल दी गई है, जिन-जिन इलाकों में कर्फ्यू में 2 घंटे की ढिल दी गई है, उन इलाकों में लोग खरीदारी करने के लिए घरों से बाहर निकल कर बाजार पहुंचे। नागपुर के शक्कर धारा इलाके में अधिकांश लोग सब्जियां और फल खरीदते हुए देखे गए।

लोगों ने बताया कि 3 दिन से किस तरीके से वह घरों में रह रहे हैं, उन्हें ही पता है। जैसे उन्हें पता लगा कि 2 घंटे के लिए कर्फ्यू में छूट मिली है तो लोग दो-तीन दिन की सब्जियां एक साथ खरीदकर ले जा रहे हैं। कुछ लोग फल खरीदते हुए देखे गए, तो अधिकांश लोग सब्जियां खरीदते हुए देखे गए। फल विक्रेता और सब्जी विक्रेताओं ने कहा कि कर्फ्यू की वजह से ठेले पर ही उनका सामान खराब होने लगा है, उन्हें उम्मीद है कि बाकी बचा हुआ सामान आज बिक जायेगा।

पुलिस ने 18 विशेष टीम गठित की पुलिस के मुताबिक, शहर की स्थिति पर निगरानी जारी है और हालात को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। बता दें कि नागपुर शहर में हुई हिंसा के आरोपियों का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने 18 विशेष टीम गठित की हैं।

विदेशी आक्रांताओं का महिमामंडन देशद्रोह जैसा : योगी आदित्यनाथ

नईदिल्ली,एजेंसी।

बहराइच. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि भारत की विरासत पर हमला करने वाले और इसके लोगों का अपमान करने वाले आक्रमणकारियों का महिमामंडन करना देशद्रोह के बराबर है. जिसे नया भारत कभी स्वीकार नहीं करेगा. महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में मुगल शासक औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर चल रहे विवाद के बीच आदित्यनाथ ने सनातन संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश करने वाले ऐतिहासिक शख्सियतों का जश्न मनाने के खिलाफ चेतावनी दी. बहराइच में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि आक्रमणकारियों का महिमामंडन करने का मतलब है देशद्रोह की जड़ों को मजबूत करना. नया भारत उन लोगों को कभी स्वीकार नहीं करेगा, जो हमारे महान पूर्वजों का अपमान करते हैं. उन लोगों की प्रशंसा करते हैं जिन्होंने हमारी सभ्यता पर हमला किया, हमारी महिलाओं का अपमान किया, हमारी आस्था पर प्रहार किया. उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया भारत की समृद्ध विरासत को स्वीकार कर रही है तो हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह हमारे सम्मान को बनाए रखे.

आदित्यनाथ की यह टिप्पणी प्रयागराज में हाल ही में संपन्न महाकुंभ पर बोलते हुए आई जिसे उन्होंने अब तक का सबसे बड़ा मानव समागम कहा. उन्होंने संसद में नरेंद्र मोदी के हालिया भाषण का भी जिक्र किया. जिसमें प्रधानमंत्री ने इस आयोजन की मेजबानी के लिए उत्तर प्रदेश की प्रशंसा की है. जिसके लिए गंगा, यमुना व रहस्यमयी सरस्वती के संगम पर 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु एकत्र हुए. उन्होंने कहा कि दुनिया में कहीं और इतना बड़ा आयोजन नहीं हुआ है. कोई भी देश इस पैमाने पर आयोजन नहीं कर सकता. महाकुंभ भारत की सनातन संस्कृति का एक प्रमाण था, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा।

जम्मू-कश्मीर में पूर्व विधायक मोहम्मद खान ने खुद को मारी गोली..!

श्रीनगर. जम्मू-काश्मीर के श्रीनगर में भाजपा के नेता व पूर्व विधायक फकीर मोहम्मद खान तुलसी बाग स्थित अपने सरकारी आवास पर मृत पाए गए. शुरुआती रिपोर्टों से पता चला है कि खान ने स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है. हालांकि आधिकारिक जांच चल रही है. फकीर मोहम्मद खान 2024 में जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में गुरेज निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था. 7246 वोट (40.34 प्रतिशत) के साथ दूसरे स्थान पर रहे. उन्हें जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता नजीर अहमद खान ने हराया. जिन्हें 8378 वोट (46.64 प्रतिशत) मिले.

कनाडा सबसे घटिया देशों में से एक – डोनाल्ड ट्रंप

ट्रंप ने फिर किया बड़ा हमला; बोले- इनसे सौदा करना मुश्किल

नई दिल्ली, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान में कनाडा के साथ व्यापारिक रिश्तों में उत्पन्न तनाव को उजागर करते हुए कहा कि कनाडा के साथ सौदा करना चुनौतीपूर्ण है। ट्रंप ने अपने एक बयान में कनाडा को 'सबसे घटिया देशों में से एक' बताया। ट्रंप ने कहा कि हम कनाडा को 51वां राज्य मानते हैं, यह टिप्पणी कनाडा को दी जाने वाली सालाना लगभग 200 बिलियन की सब्सिडी के संदर्भ में की गई। ट्रंप ने बताया कि ऐतिहासिक रूप से दोनों देशों के बीच व्यापारिक मतभेदों के कारण व्यापारिक तनाव में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी व्यापार घाटे के आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है, जबकि अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने 2024 के लिए व्यापार घाटे का अनुमान 63.3 बिलियन डॉलर बताया था। उन्होंने यह भी जोड़ा कि ÷मैं हर देश के साथ सीधे या परोक्ष रूप से डील करता हूँ,÷ और कनाडा के मामले में उन्होंने कई मौकों पर कड़े शब्दों का प्रयोग किया। उनके अनुसार, कनाडा के उत्पादों में से कुछ ऐसे हैं जिनकी अमेरिका को वर्तमान में आवश्यकता नहीं है। इस बीच, बैंक ऑफइंग्लैंड के पूर्व गवर्नर एवं अर्थशास्त्री मार्क कार्नी ने कहा कि जब तक दोनों देशों के बीच व्यापक साझेदारी पर चर्चा नहीं की जाती, तब तक ट्रंप की टिप्पणियों पर कनाडा की संप्रभुता पर सवाल उठते रहेंगे। यह बयान अमेरिकी-कनाडाई व्यापारिक रिश्तों में जारी विवाद और मतभेदों की पुष्टि करता है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक वार्तालापों और नीतिगत परिवर्तनों की संभावनाएं बनी हुई हैं।

86 साल की महिला को 2 महीने रखा डिजिटल अरेस्ट, 20 करोड़ ठगे

मुंबई, एजेंसी। साइबर फ्रॉड का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आयाहै। एक बुजुर्ग महिला को करीब 2 महीने तक डिजिटल अरेस्ट रखा और 20 करोड़ रुपये ठग लिए। इस दौरान महिला को डराया, धमकाया और बच्चों को गिरफ्तार करने की तक की धमकी दे दी। पुलिस ने इस मामले पर एक्शन लेते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। महिला को कॉल करने वाले ने खुद का नाम संदीप राव बताया और कहा कि वह एक सीबीआई ऑफिसर है। इसके बाद उसने आरोप लगाए कि विक्टिम महिला के नाम और डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके एक बैंक अकाउंट है।

दिल्ली में मंत्रियों को आवास का आवंटन शुरु

नई दिल्ली नई दिल्ली. दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार 6, फ्लैग स्टाफ रोड स्थित बंगले को राज्य अतिथि गृह के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बना रही है. जिसे भाजपा नेता शीश महल कहते हैं. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2015 से अक्टूबर 2024 तक इस बंगले में रहे. इसके जीर्णोद्धार पर 33.66 करोड़ रुपये खर्च किए. फरवरी में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने अभियान के दौरान भाजपा ने जनता के पैसे के इस व्यय के लिए केजरीवाल पर हमला करते हुए वचन दिया था कि उनके मुख्यमंत्री इस शीश महल में नहीं रहेंगे. ऐसे में रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनने के बाद शालीमार बाग में अपने पारिवारिक घर में रह रही है, जबकि भाजपा सरकार शीश महल के संसाधन का उपयोग करने के तरीकों पर विचार कर रही है. एक अधिकारी ने दिल्ली में एक राज्य अतिथि गृह की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि अन्य राज्यों की तरह शहर में ऐसा कोई भवन नहीं है।

देश | चौंकाने वाला खुलासा नागपुर हिंसा पर

नागपुर में बांग्लादेशी सोशल मीडिया अकाउंट भड़का रहे थे दंगा

एजेंसी।

नागपुर दंगा का बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आया है। पुलिस को पता चला है कि बांग्लादेश के सोशल मीडिया अकाउंट नागपुर में मुस्लिमों को हिंसा करने के लिए भड़का रहे थे। पुलिस ने इस संबंध में जाँच चालू कर दी है। पुलिस ने तमाम ऐसी पोस्ट भी हटाई हैं, जिनमें आपत्तिजनक सामग्री थी। इस बीच हिंसा के मामले में 84 लोग गिरफ्तार किए गए हैं।

पुलिस को बांग्लादेश के कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट मिले हैं, जिनसे हिंसा भड़काने की धमकियाँ दी गई थीं। अभी तक 97 सोशल मीडिया अकाउंट की पहचान की गई है। इनमें से ज़्यादातर पोस्ट बांग्लादेशी ढ्ढक्कएड्रेस वाले कंप्यूटर से किए गए थे।

ऐसे ही एक बांग्लादेशी IP एड्रेस से की गई पोस्ट में कहा गया था कि यह दंगा तो बस एक शुरुआत है। महाराष्ट्र साइबर सेल ने अफ़वाह फैलाने और हिंसा भड़काने के आरोप में 34 सोशल मीडिया अकाउंट के खिलाफ़ कार्रवाई की है। पुलिस अभी तक 10 FIR दर्ज कर चुकी है।

पुलिस ने 140 ऐसी पोस्ट सोशल मीडिया पर से हटाई हैं, जिनमें दंगा भड़काने वाली बातें लिखी हैं। नागपुर दंगे के बाद पुलिस अब धरपकड़ में भी लगी है। पुलिस ने अब तक 84 लोगों को गिरफ्तार किया है। हिंसा का मास्टरमाइंड फहीम शमीम खान भी गिरफ्तार हो गया है।

गिरफ्तार होने वालों में 8 विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी शामिल हैं। हालाँकि, उन्हें जमानत मिल गई थी। गिरफ्तार किए गए 19 आरोपितों को 21 मार्च तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। बाकी भी लोगों को पुलिस गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। गौरतलब है कि 17 मार्च को इस्लामी कट्टरपंथी भीड़ ने कुरान जलाने की अफवाह के नाम पर नागपुर में काफी उत्पात मचाया था। इस दौरान मुस्लिम भीड़ ने पुलिसवालों पर पथराव किया था। उनके पथराव में 30+ अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए थे।

मुस्लिमों ने एक महिला पुलिसकर्मी को भी दबोच कर उसके साथ छेड़छाड़ की थी और उनके कपड़े फाड़ने का प्रयास किया था। एक DCP पर कुल्हाड़ी से हमला हुआ था, इसमें वह गंभीर रूप से घायल हुए थे। दंगे के दौरान हिन्दुओं की दुकानों और घरों को विशेष रूप से निशाना बनाया गया था। उनकी गाड़ियाँ भी जलाई गई थी।

इस दंगे के बाद छत्रपति संभाजीनगर में औरंगजेब की कब्र पर ASI ने सुरक्षा बढ़ाई है। ASI ने बताया है कि इसके चारों तरफटिन और तार की बाड़ लगाई गई है। अब यह कब्र पूरी तरह ढक दी गई है।

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का भतीजा हुआ 'दिवालिया'

वाशिंगटन , एजेंसी।

नवाज शरीफके बेटे हसन नवाज को लंदन प्रशासन ने 2025 का डिफॉल्टर घोषित किया. वह अब दिवालिया हो चुका है. अगल महीने से उसकी संपत्ति नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का बेटा दिवालिया हो गया है. लंदन प्रशासन ने नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को वर्ष 2025 का डिफॉल्टर घोषित किया है. उसके खिलाफ अब दिवालिया की कार्रवाई अगले महीने से शुरू की जा सकती है. बता दें, हसन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का भतीजा है. वहीं, हसन की बहन पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री हैं.

लंदन प्रशासन के गैजेट के अनुसार, हसन नवाज पर करीब 10 मिलियन पाउंड का इनकम टैक्स बकाया है. 10 मिलियन पाउंड करीब 1,12,13,64,000 भारतीय रुपये होते हैं. हसन पर आरोप है कि वह जानबूझकर टैक्स की राशि नहीं चुका रहा है. अगले माह से हसन की संपत्ति को नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हसन की टैक्स राशि 2015-16 से बकाया है. अब उस पर जुर्माने सहित कुल राशि 10 मिलियन पाउंड हो गई है.

जानें क्या है मामला?

बता दें, हसन नवाज का नाम पनामा पेपर लीक मामले में भी सामने आया है. हसन और उसके परिवार के ऊपर काले धन से अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है. इसके बाद हसन ने लंदन स्थित अपनी एक संपत्ति को 38 मिलियन पाउंड में अली रियाज नाम के पाकिस्तानी व्यक्ति को बेच दिया था. अली रियाज खुद एक संदिग्ध है. कहा जाता है कि अली रियाज नवाज शरीफऔर उनके परिवार के कालेधन को सफेद बनाने में मदद करता है।

CMYK CMYK

रायपुर में महिला प्रोफेसर के साथ दुर्व्यवहार पर उठा प्रश्न

विभागीय मंत्री ने कहा 3 दिन के भीतर होगी कार्यवाही

कवर्धा। पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने आज विधानसभा में महिला के साथ दुर्व्यवहार एवं विशाखा समिति के संबंध में बहुत ही संवेदनशील विषय सदन के समक्ष रखा। इस दौरान उन्होंने वर्ष 2018 में शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर में पदस्थ प्रिंसिपल जी.आर.चतुर्वेदी द्वारा महिला प्रोफ़ेसर के साथ किये गए दुर्व्यवहार के विषय में अब तक कार्यवाही नहीं होने के संबंध में प्रश्न किया और उसमें विशाखा समिति की तत्कालीन अध्यक्ष जिन्होंने निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्यवाही की अनुशंसा की गई उनके ऊपर खुद झूठा आरोप लगाने के विषय की जानकारी भी सदन में रखी और उन्हें न्याय दिलाने की मांग की।

भावना बोहरा ने प्रश्न किया वर्ष 2018 में कांग्रेस शासन के दौरान शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर में पदस्थ संविदा प्रोफ़ेसर अनीता शर्मा द्वारा वर्तमान प्राचार्य जी.आर. चतुर्वेदी के खिलाफ दुर्व्यवहार करने की शिकायत की थी, जिसकी जांच विशाखा समिति द्वारा तत्कालीन समिति अध्यक्ष डॉ. सरोज परहाते की अध्यक्षता में की गई जिसमें प्राचार्य जी.आर. चतुर्वेदी और उनके सहयोगी सेवानिवृत्त शांति किशोर मांझी को दोषी पाया गया था। लेकिन अधिकारियों द्वारा इसकी जांच अभी तक लंबित हैं और इसमें दोषियों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। भावना बोहरा ने कहा कि विशाखा समिति की जांच में प्राचार्य जी.आर.चतुर्वेदी को दोषी पाया गया परन्तु तत्कालीन समय में डॉ. सरोज परहाते को षड्यंत्रपूर्वक विशाखा समिति से हटा दिया गया एवं उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए वहीं दोषी प्राचार्य का प्रमोशन कर दिया गया। आज 8 वर्ष हो गए हैं लेकिन अनीता शर्मा को अब तक न्याय नहीं मिला है वहीं दोषी का प्रमोशन कर दिया गया है इसके खिलाफ जल्द से जल्द जांच पूरी कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग भावना बोहरा ने सदन के समक्ष की।

भावना बोहरा के प्रश्न का प्रतिउत्तर देते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी ने कहा कि वर्ष 2018 में हुई यह घटना बहुत ही संवेदनशील है और इस शिकायत की जांचकर्ता डॉ. सरोज परहाते पर भी झूठे आरोप लगाए गए हैं। यह संवेदनशील विषय है और उन दोनों महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है और 9 जनवरी 2023 को माननीय उच्च न्यायालय ने इस विषय को संज्ञान में लेते हुए पुनः जांच करने के निर्देश दिए जिसकी पुनः विशाखा समिति द्वारा जांच की गई और उस जांच की रिपोर्ट शासन के पास आ चुकी और जांच रिपोर्ट में अनुशंसा की गई है कि प्राचार्य जी.आर.चतुर्वेदी को अन्यत्र स्थान्तरण करने एवं जो समाचार पत्रिका है उसपर जनसंपर्क के माध्यम से कार्यवाही करने हेतु समिति ने अनुशंसा की है साथ ही उनके सहयोगी जो रिटायर्ड हो चुके हैं शांति किशोर मांझी पर भी नियमानुसार कार्रवाई होगी और यह कार्रवाई 3 दिनों के भीतर की जाएगी।भावना बोहरा ने स्वास्थ्य सुविधाओं एवं सेवाओं के संबंध में प्रश्न पूछा कि वर्ष 2023 से 1 फ़रवरी, 2025 तक कबीरधाम जिले अंतर्गत पंजीकृत प्राइवेट हॉस्पिटलों में आयुष्मान कार्ड एवं राशन कार्ड से इलाज संबंधित कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? उन पर क्या कार्रवाई की गई? क्या आयुष्मान कार्ड एवं राशन कार्ड से राशि समायोजित करने के उपरांत नगद राशि लेने का प्रावधान है? यदि हां तो किस नियम तक के तहत राशि ली जाती है? यदि राशि लेने का प्रावधान नहीं है तो इससे संबंधित प्राप्त शिकायतों पर प्राइवेट अस्पतालों के ऊपर नियमों के तहत क्या-क्या कार्रवाई की गई? जिसके लिखित प्रतिउत्तर में माननीय लोक स्वास्थ्य मंत्री जी ने बताया कि वर्ष 2023 से 01 फ़रवरी, 2025 तक कबीरधाम जिला अंतर्गत पंजीकृत प्राइवेट हॉस्पिटलों में आयुष्मान कार्ड एवं राशन कार्ड से इलाज संबंधित कुल 06 शिकायतें प्राप्त हुई है। जिनके ऊपर नियमानुसार कारण बताओ नोटिस एवं स्पष्टीकरण माँगा गया है। आयुष्मान कार्ड एवं राशन कार्ड से राशि समायोजित करने के उपरांत नगद राशि लेने का प्रावधान नही है । प्राप्त शिकायतों पर प्राइवेट हॉस्पिटलों से स्पष्टीकरण लिया जाता है एवं संबंधित हितग्राहियों को राशि वापस दिलाया गया है तथा चेतावनी पत्र प्रेषित किया गया है। भावना बोहरा ने मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के संबंध में प्रश्न करते हुए पूछा कि जिला कबीरधाम अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के तहत वर्ष 2024-25 में 15 फ़रवरी 2025 तक कितनी सड़कों की स्वीकृति प्राप्त हुई है एवं इस हेतु कितनी राशि की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है ? स्वीकृत सड़कों में से कितनी लम्बाई की कितनी सड़कों का निर्माण किया जा चुका है? कितनी सड़कों का निर्माण प्रक्रियाधीन है?

नहीं चलेगी पेशी पर पेशी, निर्धारित समय सीमा में निपटाएं राजस्व प्रकरण

लंबित राजस्व प्रकरणों पर कलेक्टर सख्त, दिए निर्देश

वरिष्ठ अधिकारियों को अधीनस्थ कार्यालयों के निरीक्षण के निर्देश

धमतरी । जिले में लंबित राजस्व प्रकरणों को लेकर आज कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा ने अधिकारियों के प्रति नाराजगी व्यक्त की और उचित प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों की बैठक में कामकाज की विस्तृत समीक्षा की। कलेक्टर ने इस दौरान नामांतरण, अविवादित बंटवारा, विवादित राजस्व प्रकरणों, अभिलेख दुरूस्ती और त्रुटि सुधार प्रकरणों, भू-अर्जन, सीमांकन सहित डायवर्सन प्रकरणों की जानकारी ली। कलेक्टर ने इन सभी प्रकरणों की राजस्व अधिकारी न्यायालयवार समीक्षा की। श्री मिश्रा ने बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों पर नाराजगी जताई और सीमांकन, बटांकन, नामांतरण जैसे प्रकरणों में भी निर्धारित समय से अधिक अभी तक पेशी पर पेशी बुलाने पर रोक लगाने की बात कही। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री आंजनेय वार्ष्णेय, अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों सहित सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार भी मौजूद रहे।

कलेक्टर ने निर्देशित किया कि सभी राजस्व प्रकरणों में शासन द्वारा निर्धारित समयावधि में ही निपटारा सुनिश्चित किया जाए। पेशी पर पेशी अब नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि बार-बार पेशी पर बुलाने से हितग्राहियों को काफी परेशानी होती है। ना केवल उनका पैसा-समय बर्बाद होता है, बल्कि वे अन्य जरूरी काम भी नही कर पाते हैं। कलेक्टर ने पेशियों में कमी लाते हुए राजस्व प्रकरणों का निर्धारित समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने सभी प्रकरणों को ई-कोर्ट में दर्ज करने के निर्देश दिए।

किसान पंजीयन और पीएम इंटर्नशिप में कम पंजीयन पर कलेक्टर ने जताई नाराजगी

अगले तीन दिनों में प्रगति लाने दिए सख्त निर्देश, पंजीयन नहीं करने वाले लोक सेवा केन्द्रों पर होगी कार्रवाई

धमतरी। कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा ने समय सीमा की साप्ताहिक बैठक में आज किसान पंजीयन और पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए हितग्राहियों के लक्ष्य अनुसार पंजीयन नहीं होने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इन दोनों योजनाओं में अगले तीन दिनों में खासी प्रगति लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिए कि इन दोनों योजनाओं में पंजीयन नहीं करने या पंजीयन करने में लापरवाही बरतने वाले लोक सेवा केन्द्रों के संचालकों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने ऐसे लोक सेवा केन्द्रों की आईडी तक बंद करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने इसकी पूरी मॉनिटरिंग करने के लिए अपर कलेक्टर श्रीमती इंदिरा देवहारी को नोडल अधिकारी भी बनाया।

समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने जिले में संचालित विभिन्न विभागों की योजनाओं और जनहितकारी कार्यक्रमों की भी समीक्षा की। उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनाने की धीमी गति पर भी नाराजगी जताई। कलेक्टर ने 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाने के लिए गांववार शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस काम में ग्राम स्तर पर मितानिन और बीएलई की मदद लेने को भी कहा। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अमले की सहायता से ऐसे हितग्राहियों को लोक सेवा केन्द्रों तक ले जाकर अगले एक सप्ताह में सभी पात्र लोगों के आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी लोक सेवा केन्द्रों में बोर्ड लगाकर आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाने की जानकारी भी प्रदर्शित करने को कहा। स्मय सीमा की साप्ताहिक बैठक में कलेक्टर ने आज धमतरी शहर की तीन सड़कों के चौड़ीकरण और उन्नयन के लिए जल्द से जल्द सर्वे शुरू करने के निर्देश दिए। अम्बेडकर चौक से रूद्री, सिहावा चौक से नहर-नाका रोड चौक और रत्नाबांधा से मुजगहन तक की इन तीनों सड़कों के चौड़ीकरण के लिए उन्होंने लोक निर्माण विभाग और नगरनिगम के अधिकारियों को आपसी

तीन लोगों की मौके पर मौत, सड़क किनारे टहल रहे थे सभी, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार

धमतरी । छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से सड़क हादसे का मामला सामने आया है यहां पर बेकाबू स्कॉर्पियो ने सड़क किनारे टहल रहे लोगों को कुचल दिया। इस दौरान मौके पर ही तीन लोगों की मौत हो गई है। स्कॉर्पियो की स्पीड अधिक होने के कारण वह लोगों को रौंदते हुए अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी। मामले में आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना बीती रात एनएच 30 पर दरबा गांव की है। वहीं यह पूरा मामला बिरेझर चौकी क्षेत्र का है।वहीं बैकुंठपुर के सोनहत के अंतर्गत आने वाले ग्राम कटगोड़ी में भीषण सड़क हादसे में चार युवकों की मौत हो गई। हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। घटना पास में लगे ष्टष्टञ्जङ्क में रिकार्ड हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों बाइकों की गति काफी तेज थी। शुरुआती जांच में दुर्घटना का मुख्य कारण ओवर स्पीड और लापरवाही पूर्वक वाहन चलाना बताया जा रहा है। हादसे में अमित कुमार प्रजापति निवासी कछार, कृष्ण कुमार, रोहित चौधरी राहुल पनिका की मौत हो गई। वहीं हादसे में एक अन्य युवक को गंभीर चोटे आई है, जिसका उपचार जारी है। शनिवार की देर शाम सोनहत ब्लॉक के कटगोड़ी में दो बाइकों के बीच भीषण टक्कर में चार युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह हादसा तेज रफ्तार और लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने के कारण घटित हुई है।

हितग्राहीमूलक योजनाओं में शत-प्रतिशत हो स्वीकृति एवं वितरण, लंबित प्रकरण 25 मार्च तक निराकृत हों

डीएलसीसी की बैठक में कलेक्टर श्री मिश्रा के निर्देश

धमतरी । कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा ने आज जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में अधिकारियों को हितग्राहीमूहक विकास-सह-रोजगार योजनाओं के प्रकरणों में शत्-प्रतिशत स्वीकृति के साथ सहायता ऋण राशि का वितरण भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले के हितग्राहियों को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का पूरा लाभ दिलाने को भी कहा। श्री मिश्रा ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित इस बैठक में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए संचालित योजनाओं में लक्ष्य अनुसार प्रगति नहीं होने पर भी बैंक अधिकारियों के प्रति चिंता व्यक्त की। उन्होंने हितग्राहियों के सभी लंबित सहायता-ऋ ण स्वीकृति प्रकरणों को 25 मार्च तक निराकृत करने के भी निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने बैंकों के माध्यम से हर साल किए जाने वाली बीमा योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने बैंकों को ऐसे बीमा प्रकरणों में बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर जल्द से जल्द क्लेम उनके परिजनों-आश्रितों को दिलाने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने वार्षिक शाख योजना की प्रगति, बीमा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा, पीएमएमवाय, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, केसीसी हेतु बैंकों के भेजे गये प्रकरण, प्रगति, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा बैंकों को प्रेषित किये गये प्रकरण, प्रधानमंत्री सूक्ष्य उद्योग उन्नयन योजना, रोजगार सृजन योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि,आजीविका मिशन, लिंकेज और प्रकरणों की बारी-बारी से जानकारी ली। बैठक में उन्होंने उपस्थित बैक अधिकारियों से सीएसआर मद से किये जाने वाले कार्यो की जानकारी ली और निर्देशित किया कि सभी बैंक जिले में सीएसआर मद से कार्य करने आगे आयें। कलेक्टर ने बैंकिंग कार्य की समीक्षा करते हुए जिलो में संचालित कुल बैंकिंग शाखाओं, कुल जमा, कुल ऋण राशि, जमा-ऋण अनुपात, कृषि ऋण, लघु उद्योग, कमजोर क्षेत्र के ऋण, अल्प संख्यक समुदाय, महिलाओं के लिए ऋण सहित अन्य विभागीय कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। बैठक में एलडीओ श्री नवीन कुमार तिवारी, एलबीएम श्री इंदर कुमार केलवानी के अलावा विभिन्न बैंकों के प्रबंधक उपस्थित थे।

नशीली पदार्थों के अनाधिकृत विक्रय पर सख्त कार्रवाई की जाएगीः कलेक्टर

मेडिकल दुकानों में अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएं - पुलिस अधीक्षक श्री सिंह

स्वापक औषधि मनः प्रभावी पदार्थो के नियंत्रण हेतु जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक

महासमुंद। स्वापक औषधि मनः प्रभावी पदार्थों के अनाधिकृत व्यवसायियों पर व्यापक और प्रभावी नियंत्रण हेतु जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आज यहाँ कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष सिंह भी मौजूद थे। कलेक्टर श्री लंगेह ने कहा कि ऐसे स्वापक औषधि मनः प्रभावी पदार्थ के अनाधिकृत व्यवसायियों पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि यह ज़िला ओड़िसा राज्य की सीमा से लगे होने के कारण अनाधिकृत व्यवसायियों द्वारा ऐसे औषधियों के क्रय-विक्रय की संभावना बनी रहती है। पुलिस द्वारा कार्रवाई भी की जाती है। आप भी इस पर नज़र रखे तो अंकुश लगेगा। उन्होंने नगरीय निकायों में कचरा संग्रहण केन्द्रों में विशेष रूप से बायो मेडिकल वेस्ट, सीरिंज या टेबलेट पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष सिंह ने कहा जिले में स्वापक औषधि मनः प्रभावी पदार्थ के रोकथाम के लिए दवा व्यवसायियों की बैठक लेकर दिशा-निर्देश दें तथा निगरानी की जाए। स्वापक औषधि मनः प्रभावी पदार्थ जो किसी रोग उपचार हेतु दवाईयों की श्रेणी में आते हैं। क्रय-विक्रय पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाए एवं उल्लंघन करते पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रत्येक मेडिकल दुकानों में सीसीटीवी कैमरा भी अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों और मैदानी अमलों में भी इस संबंध में विशेष निगरानी रखी जाए। स्कूल, कॉलेजां में भी समन्वय कर जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कोटप्पा एक्ट की कार्रवाई बढ़ाने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट निर्देश दिए है कि नशीली पदार्थों के अनाधिकृत विक्रय करते पाए जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें।

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिले में नशीली दवाओं के दुरूपयोग और उसके व्यापार पर सभी कारगर कदम उठाएं। जिले के सीमावर्ती इलाकों में कड़ी नजर रखी जाए। उन्होंने कहा कि ज्यादातर अपराध नशा की वजह से होते है। उन्होंने कहा कि स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ जो किसी रोग उपचार हेतु मेडिसिन के वर्ग में आते है, इसके क्रय-विक्रय पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन कड़ी निगरानी रखें। सहायक औषधि नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने इस संबंध में जानकारी दी। बैठक में समिति सदस्य, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी, उप संचालक समाज कल्याण, महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

माल वाहक वाहनों में सवारी न ढोएं

बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष सिंह ने कहा कि जिले में लगातार सड़क दुर्घटनाओं में इजाफा हो रहा है। जिसका मुख्य कारण सीट बेल्ट या हेलमेट नहीं पहनना है साथ ही मादक द्रव्यों का सेवन भी एक महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने अपील किया कि सभी नागरिक एवं शासकीय अधिकारी-कर्मचारी वाहन चलाते समय सीट बेल्ट या हेलमेट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें अन्यथा उन पर भी चालानी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मालवाहक वाहनों जैसे पिकअप, ट्रैक्टर, ट्रक आदि का सवारी वाहनों के रूप में प्रयोग नहीं करने के निर्देश दिए।

चिरायु से गर्वित को जन्मजात विकृति से मिली निजात

रायपुर के निजी अस्पताल में होंठ एवं तालू का कराया गया निःशुल्क ऑपरेशन

परिजनों ने मुख्यमंत्री का जताया आभार

जशपुरनगर । जिले के बीटीआई पारा के गर्वित सिंह अभी केवल 01 साल के है। जन्म के साथ ही उनके होंठ एवं तालू में विकृतियां थी। इससे उनके माता-पिता में चिंता व्याप्त हो गई और बच्चें के इलाज और उसमें होने वाले खर्चे को लेकर सोच में पड़ गए। ऐसे में अस्पताल के डॉक्टरों के द्वारा चिरायु योजना की जानकारी दी गई। चिरायु के जिला नोडल अधिकारी श्री अरविंद रात्रे ने परिजनों को चिरायु योजना की जानकारी देने के साथ ही बच्चों को इससे मिलने वाली निःशुल्क इलाज के संबध में बताया। इससें परिजनों को काफी राहत मिली।

गर्वित को बेहतर इलाज के लिए रायपुर स्थित ओम हॉस्पिटल शासकीय व्यय पर भेजा गया। जहां डॉक्टरों ने बताया की बच्चे का ऑपरेशन करना अधिक कारगर होगा। जिसे देखते हुए डॉक्टरों ने परिजनों से चर्चा कर बच्चे के पहला ऑपरेशन 6 माह होने पर उसके होंठ का किया गया।

इसके बाद बच्चे के आठवें माह मे तालू का ऑपरेशन किया गया। जिसके बाद बच्चे का चेहरा सामान्य हो गया। इससे उनके परिजन काफी खुश हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और डॉक्टरों के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों के लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है। सरकार ने गरीबों की पीड़ा को समझा और इलाज के लिए बेहतर संस्थानों में भेजकर निःशुल्क इलाज करा रही है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वास्थ्य परीक्षण कर चिरायु की टीम लगातार जांच कर बच्चों बेहतर इलाज कराया जा रहा है। चिरायु की टीम के द्वारा कटे-फटे होंठ, जन्म जात मोतियाबिंद, टेढ़े-मेढ़े हाथ पैर, श्रवण बाधा सहित 44 प्रकार की बीमारी तथा विकृति पर कार्य किया जाता है। बच्चों को उच्च स्तर की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराकर उसका निःशुल्क उपचार कराया जाता है। जरूरत पड़ने पर बच्चों को उच्च स्थान पर रेफर भी कराया जाता है।

कलेक्टर ने ली समय-सीमा की बैठक, नियद नेल्लानार योजना की एंट्री एवं सेचुरेशन की हुई

आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए 60 से 70 साल आयु के बुजुर्गों हेतु लगाएं विशेष शिविर- कलेक्टर श्री चतुर्वेदी

दंतेवाड़ा । कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी ने मंगलवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक ली। बैठक में उन्होंने नियद नेल्लानार योजना की एंट्री एवं सेचुरेशन प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि जन्म प्रमाण पत्र, हर घर जल, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, व्यक्तिगत शौचालय, महात्मा गांधी नरेगा में मांग के आधार पर 100 प्रतिशत जॉब कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, लघु वनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदी, वन अधिकार पट्टा सेचुरेशन, सभी हाउसहोल्ड को विद्युतीकरण, आयुष्मान कार्ड निर्माण एवं वितरण, गर्म भोजन-टीएचआर, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना,आंगनबाड़ी हितग्राही पंजीयन,टीबी स्क्रीनिंग, उज्ज्वला योजना, श्रमिक पंजीयन कार्ड, एनसीडी स्क्रीनिंग एवं मॉनिटरिंग, जननी सुरक्षा, एएनसी पंजीयन एवं जांच, पशु टीकाकरण, एम्युनाईजेशन, पाठ्य पुस्तक वितरण, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना, प्राथमिक शाला एनरोलमेंट, स्कूल गणवेश, सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत विधवा पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना सहित राईट टू स्किल, जनधन खाता, आधार कार्ड, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना तथा राशन कार्ड की उपलब्धता शत-प्रतिशत सुनिश्चित करने के निर्देश सम्बंधित अधिकारियों को दिए। इसके साथ ही केंद्र शासन एवं राज्य शासन की विभागीय योजनाओं को मिशन मोड में क्रियान्वयन करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए 60 से 70 वर्ष के बुजुर्गों के लिए विशेष शिविर लगाए जाने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए हैं। इन शिविरों का उद्देश्य उन बुजुर्गों को चिह्नित करना है जो इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के योग्य हैं।

इससे बुजुर्गों को मुफ्त या सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा बैठक में एफएसटीपी मल-कीचड़ उपचार संयंत्र को

भेलवा तालाब में दीमक लगे पेड़ों पर चुना एवं पोटैशियम परमैंगनेट से पोताई नगर निगम ने किया

भिलाईनगर। नेहरू नगर भेलवा तालाब का प्रमुख आकर्षण वहां के पुराने कतारबद्ध लगे हुए विभिन्न प्रकार के आकर्षक वृक्ष है, जो सभी के मनो को मोह लेते है। नगर निगम भिलाई आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय, जोन आयुक्त अजय सिंह राजपूत के साथ भेलवा तालाब संधारण से संबंधित चर्चा के लिए गये हुए थे। वहीं पर योगा, प्रणायाम करने वाले शैलेन्द्र सिंग, जितेन्द्र सिंग, कवित्री संध्या श्रीवास्तव, प्रदीप डालमिया, डां ललित पोपट ने शिकायत की पेड़ो के ऊपर दीमक लग रहे है। जिससे कुछ ही दिनो में अच्छे खासे हरे-भरे पेड़ सूख जायेगे, दीमक बहुंत खतरनाक होते है, सब पेड़ो को नुकसान पहुचायेगें, समय पर इसका निदान करना जरूरी है।

आयुक्त पाण्डेय ने उद्यान अधिकारी तिलेश्वर साहू को वहीं से फोन करके तुरन्त इसका निदान करने के लिए आदेशित किये। आदेशानुसार दीमक लगे पेड़ो के ऊपर चुना एवं पोटैशियम परमैंगनेट से पोताई की जा रही है, इससे दीमक की समस्या का समाधान हो जायेगा।

कलेक्टर लंगेह ने समय सीमा की बैठक में दिए महत्वपूर्ण निर्देश

मनरेगा के तहत श्रम आधारित कार्य स्वीकृत करने के निर्देश

महासमुंद। कलेक्टर श्री विनय लंगेह ने समय सीमा की बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में धान उठाव, ई-केवाईसी, 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा, डिजिटल क्रॉप सर्वे, पीएम जनमन योजना, हीट वेव से बचाव और मनरेगा में श्रम आधारित कार्य जैसे अहम मुद्दों की समीक्षा की गई। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री एस. आलोक, अपर कलेक्टर श्री रवि कुमार साहू, रविराज ठाकुर, एसडीएम श्री हरिशंकर पैकरा सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे एवं वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अनुविभागीय एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी जुड़े थे।

कलेक्टर श्री लंगेह ने खाद्य विभाग और संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया कि धान उठाव की प्रक्रिया शीघ्रता से पूरी की जाए, जिससे किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। पीएम किसान सम्मान निधि और अन्य योजनाओं के तहत लाभार्थियों की ई-केवाईसी प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए कि वे सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करें।कलेक्टर ने डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि यह सर्वे समय पर पूरा किया जाए ताकि योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभार्थियों को मिल सके। जहां प्रारम्भ नहीं हुए हैं वहां प्रारम्भ करने के निर्देश भी दिए गए। इसी तरह प्रधानमंत्री जनमन योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे इस योजना के लक्ष्यों को शीघ्रता से पूरा करें। उन्होंने गर्मी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए, हीट वेव से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने, सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को सतर्क रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़कों पर आवारा मवेशियों के जमवाड़ा को सुरक्षित स्थानों पर रखने के निर्देश दिए गए।

कलेक्टर श्री लंगेह ने मनरेगा के तहत अधिकतम श्रम आधारित कार्यों को स्वीकृति देने के निर्देश दिए गए, जिससे ग्रामीणों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध हो सके एवं ग्रामीणों को बिना वजह पलायन न करना पड़े। इसके अलावा, विभिन्न सरकारी योजनाओं और समय सीमा पत्रकों की विस्तार से समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे सभी योजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करें ताकि आमजन को इनका लाभ जल्द से जल्द मिल सके। बैठक में कलेक्टर ने सभी विभागों को कार्य में पारदर्शिता और तत्परता बनाए रखने का निर्देश दिया।

सहायक शिक्षकों का फिर से प्रदर्शन, नया रायपुर धरना स्थल से मंत्रालय तक किया कदमताल, निकाली रैली

दैनिक लोकशक्ति,रायपुर । समायोजन की मांग के साथ बर्खास्त किये गये बीएड सहायक शिक्षकों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने रैली निकालकर अपना विरोध प्रकट किया।

बर्खास्त शिक्षकों ने यह पूरा प्रदर्शन अनुसूचित जाति शासकीय सेवक विकास संघ के बैनर तले किया। यह रैली नया रायपुर धरना स्थल से मंत्रालय तक पहुंची। यहाँ सुरक्षा में तैनात पुलिकर्मियो ने उन्हें बैरिकेट लगाकर रोक दिया। इस दौरान वे लगातार नारेबाजी करते रहे। प्रदर्शनकारी बर्खास्त शिक्षकों का कहना है कि, जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती उनका धरना प्रदर्शन ,आंदोलन जारी रहेगा।

गौरतलब है कि, छत्तीसगढ़ के 2,897 बर्खास्त बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक एक बार फिर से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। नौकरी से निकाले गए यह शिक्षक अपना बोरिया-बिस्तर लेकर नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर जमा हो गए हैं। सरकार के खिलाफ इन्होंने नारेबाजी की है। शिक्षकों का कहना है सरकार ने कमेटी बना दी है लेकिन फैसला करने में सुस्ती दिखा रही है। उनका कहना है कि हमारी मांग है कि कि इस मामले में जल्दी फैसला किया जाए।समायोजन की मांग को लेकर लम्बे समय तक धरना, प्रदर्शन, आंदोलन करने वाले प्रदेश भर के बीएड सहायक शिक्षकों ने एक बार फिर से नया रायपुर में धरना शुरू कर दिया है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने करीब 2800 बीएड सहायक शिक्षकों को बर्खास्त किया था। इस बीच नगरीय निकाय

चुनाव के लिए आचार संहिता लगने पर इन्होंने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया था। अब यह फिर से धरने पर बैठ गए हैं।इससे पहले भी 45 से ज्यादा दिनों तक शिक्षक प्रदर्शन में बैठे थे। लेकिन नगरीय निकाय की आचार संहिता लगने के कारण उन्होंने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया था। अब फिर से प्रदर्शन करने का मतलब है कि सरकार ने जो कमेटी बनाई है उसका फैसला तुरंत होना चाहिए। शिक्षकों का कहना है कि अगर सरकार हमें फिर से नियुक्त नहीं किया तो घर के बाहर निकलने से पहले उसकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी लेनी होगी।

राज्य स्तर पर खराब रैंकिंग पर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर किया अधिकारियों को रैंकिंग सुधारने दिये कड़ी निर्देश

मोहला। कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने जिला कार्यालय के सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। कलेक्टर ने शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, सेवाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी अधिकारी योजनाओं का बेहत्तर क्रियान्वयन करते हुए अधिक से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित करना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने इस दौरान राज्य स्तर पर विभिन्न योजनाओं के रैंकिंग की समीक्षा की। कुछ योजनाओं रैंकिंग में अपेक्षित प्रगति में कमी पर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारियों को रैंकिंग सुधारने के कड़ी निर्देश दिए। कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जिलाधिकारी की जवाबदेही है कि सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में रैंकिंग सुधार लाएं अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें।कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिले में बाल विवाह प्रथा को रोकने के लिए सघन जागरूकता अभियान चलाएं। उन्होंने कहा कि सभी ग्राम पंचायत में बाल विवाह जैसे सामाजिक कुप्रथा को रोकने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाएं। कलेक्टर ने आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन में बच्चों को प्रदाय किये जाने वाले रेडी टू ईट एवं पूरक पोषण आहार की निगरानी के साथ ही पोषणयुक्त आहार का वितरण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भोजन बनाने वाले कर्मियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे स्वादिष्ट और गुणवत्ता युक्त पोषण आहार वितरण किया जा सके। कलेक्टर ने बैठक में श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को प्रदान किए जाने वाले छात्रवृत्ति योजना का लाभ सभी पंजीकृत हितग्राहियों को मिले इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करें। श्रम विभाग द्वारा संचालित विभागीय योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए आवश्यक कोचिंग की व्यवस्था करने के साथ ही विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने के लिए विषय विशेषज्ञों से मार्गदर्शन और टिप्स दिलाने के निर्देश दिए।कलेक्टर ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना की समीक्षा की। भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार लंबे समय से गैस की रिफिलिंग नहीं कराने और ई केवाईसी नहीं कराने वाले हितग्राहियों को नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस तामील होने पर संबंधित हितग्राहियों को अपने नज़दीकी गैस एजेंसी में जाकर ईकेवाईसी और रिफिलिंग कराना अनिवार्य होगा।

ईकेवाईसी और रिफिलिंग नहीं कराने की दशा में संबंधित हितग्राही का उज्जवला गैस कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करने की कार्रवाई किया जाएगा। कलेक्टर ने बैठक में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि वास्तविक पात्र हितग्राहियों की पंजीयन और लाभान्वित हो रहे हितग्राहियों की सूची का मिलान करें। ऐसे हितग्राहियों जिसे योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो इस दशा में उन्हें योजना से लाभान्वित करने के निर्देश दिए गए हैं।

राशन वितरण में लाखों की अनियमितता, प्रबंधक-विक्रेता गिरफ्तार

बिलासपुर-रायपुर । शासकीय राशन के वितरण में गड़बड़ी करने वाले प्रबंधक और विक्रेता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इन पर 10 लाख रुपये की अनियमितता के आरोप में कार्रवाई हुई है. इस मामले में दो फूड इंस्पेक्टर को भी कलेक्टर ने नोटिस जारी किया है. यह मामला मस्तूरी के शासकीय उचित मूल्य की दुकान का है. मस्तूरी ब्लॉक में पीडीएस चावल गबन करने के मामले में संचालक प्रबंधक मनोज रात्रे और विक्रेता मनीराम कुर्रे पर सरकारी राशन में गड़बड़ी का आरोप लगा था. खाद्य विभाग ने जांच में दुकान संचालक और विक्रेता पर 10 लाख 82 हजार 720 रूपए की गड़बड़ी का आरोप सही पाया गया था.

दरअसल, वर्ष 2024 में शासकीय उचित मूल्य दुकान मस्तूरी आईडी 402002001 के प्रबंधक मनोज रात्रे तथा विक्रेता मनीराम कुर्रे था. उनके द्वारा राशन दुकान में चावल 272.50 क्विंटल कम, शक्कर 3.77 क्विटल अधिक एवं रिफाइंड नमक 8.04 क्विटल अधिक पाया गया. उपरोक्त राशि 1082720.23 है, इस राशि की अनियमितता इनके द्वारा की गई थी. मस्तूरी, रिस्दा, सलौनी और पोड़ी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली तहत संचालित राशन दुकान में जांच के दौरान अनियमितता पाई गई थी. इस मामले को लंबे समय से दबाकर रखने के आरोप में दो खाद्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया है. मस्तूरी में संचालित राशन दुकान के संचालक और विक्रेता पर कार्रवाई की गई वहीं बाकी तीन दुकानों में खाद्यान्न की भरपाई करने का दावा किया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने राजस्व विभाग से भौतिक सत्यापन कराने कहा है.

जेल पहुंचे पीसीसी प्रभारी सचिन पायलट ने की कवासी लखमा से मुलाकात

कवासी लखमा दिलेरी से झेल रहे कष्ट-महंत, दीपक बैज, देवेंद्र यादव सहित कई नेता पहुंचे जेल

रायपुर । छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट आज सेंट्रल जेल पहुंचे, जहां उन्होंने जेल में बंद पूर्व मंत्री कवासी लखमा से मुलाकात की. इस दौरान उनके साथ नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, विधायक देवेंद्र यादव समेत कई अन्य कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे. जेल में कवासी लखमा से मुलाकात के बाद सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत में भाजपा सरकार पर तीखे हमले किए. उन्होंने कहा कि जो लोग भाजपा की विचारधारा का विरोध करते हैं, सरकार उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करती है. हम न्यायालय में लड़ाई लड़ते रहेंगे. लोगों का चरित्र हनन करने की कोशिश की जाती है. सरकारी द्वारा एजेंसी के माध्यम से मनोबल तोड़ने की कोशिश की जाती है. हमें पूरा विश्वास है कि हमें न्यायालय के माध्यम से विजय मिलेगी. हमारा पोलिटिकल संघर्ष जारी रहेगा. सरकारी एजेंसी का धड़ल्ले से दुरुपयोग हो रहा है. ये व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं, हम इसका

पुरजोर विरोध करेंगे, पूरे देश में जहां-जहां बीजेपी सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है. वहां वहां विरोध करेंगे. नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शासन की ओर से जो भी कष्ट मिल रहा है. उसे बड़े दिलेरी के साथ कवासी लखमा झेल रहे हैं. उनमें झेलने की ताकत है. जो वह सह रहे हैं वो सरकार की प्रताड़ना है. केंद्रीय और राज्य सरकार की प्रताड़ना को झेलने में कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं. चरणदास महंत ने कहा कि हमारे प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट और अन्य पदाधिकारी भी उनसे मिलने आए थे.

सेक्स सीडी कांड में पूर्व मुख्यमंत्री बघेल के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर

रायपुर । छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सेक्स सिटी कांड में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट में आज मंगलवार को पुनर्विचार याचिका दायर की है। अब इस मामले की सुनवाई 4 अप्रैल को रायपुर कोर्ट में होगी। बता दे कि सीबीआई कोर्ट ने भूपेश बघेल को जिन आरोपों से बरी किया था, सीबीआई ने उन्हीं आरोपों को पुनः चुनौती दी है।

मरीन ड्राइव में नहीं नजर आएंगे टॉय ट्रेन और कार, निगम ने किया जब्त

रायपुर । तेलीबांधा तालाब पाथ-वे, जिसे मरीन ड्राइव के नाम से जाना जाता है, वहां नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। निगम ने फुटपाथ पर अवैध रूप से संचालित टॉय ट्रेन और टॉय कार को जब्त कर लिया गया। इसके अलावा, स्प्री वॉक कंपनी द्वारा उपयोग किए जा रहे कई अन्य सामान भी बड़ी संख्या में जप्त किए गए।दरअसल मरीन ड्राइव पर वॉक के लिए आने वाले लोगों की शिकायत लंबे समय से नगर निगम तक पहुंच रही थी। उनका कहना था कि पाथ-वे पर अवैध रूप से चल रही कमर्शियल गतिविधियों के कारण मॉर्निंग और इवनिंग वॉक में दिक्कत हो रही है। खासकर टॉय ट्रेन और टॉय कार के संचालन से उन्हें टहलने में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। निगम में सरकार बदलने के बाद नगर निगम ने इस मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत कार्रवाई की।

सीमांकन करने किसान से रिश्वत की मांग

बिलासपुर-रायपुर। सीमांकन के एवज में किसान से रिश्वत लेते सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद कोटा एसडीएम व् आईएएस तन्मय खन्ना ने रिश्वतखोर पटवारी को निलंबित कर दिया है।

रिश्वत मांगने का वीडियो हुआ था वायरल :

रतनपुर तहसील के ग्राम पचरा निवासी केवल दास मानिकपुरी के पिता स्व. दुलमदास को 1984-85 में सरकारी पट्टा मिला था। जमीन का ऑनलाइन रिकॉर्ड अपडेट कराने के लिए पटवारी अनिकेत साव ने पहले तो 60,000 की डिमांड रखी। बाद में 26 दिसंबर 2024 को पटवारी ने अपने घर पर 30,000 नगद ले लिया। जिसका केवल दास ने वीडियो भी बना लिया था। इधर पैसा लेने के बावजूद न तो जमीन का ऑनलाइन रिकॉर्ड अपडेट हुआ और न ही ऋण पुस्तिका मिली। केवल दास ने पटवारी से संपर्क किया, तो पटवारी बहाने

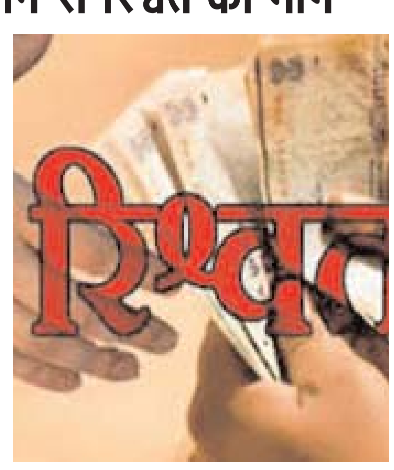

बनाकर टालने लगा। परेशान ग्रामीण ने मामले की शिकायत अनुविभागीय अधिकारी कोटा से की है और पटवारी पर धोखाधड़ी व भ्रष्टाचार की कार्रवाई की मांग की है। साथ ही अपने 30 हजार वापस दिलाने की भी गुहार लगाई है। जिसके बाद अब प्रशासन ने पटवारी को निलंबित कर दिया है।

चौथी लाइन के लिए रोके जाएंगे 46 ट्रेनों के पहिए, कुछ बदले रुट से चलेंगी

रायपुर। रेल प्रशासन ने पिछले पांच वर्षों में बिलासपुर से झारसुगुड़ा चौथी लाइन, बिलासपुर से कटनी मुरवारा सेक्शन के बीच पेण्ड्रारोड, अनूपपुर से कटनी तीसरी लाइन, रायपुर से नागपुर के बीच चौथी लाइन का कार्य करने के लिए 7 हजार से अधिक यात्री ट्रेनों के पहियों को रोककर करोड़ों की संख्या में यात्रियों का सफर प्रभावित किया है।

रेलवे के अनुसार अधोसंरचना का कार्य पूरा होने के बाद यात्री गाडियों के आवागमन समय सारिणी के साथ होने पर यात्रियों को सुविधा मिलेगी, लेकिन वर्तमान में यात्री ट्रेनो के

रद्द होने से हलाकान हो रहे हैं।

बिलासपुर से झारसुगुड़ा के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन एक महत्वपूर्ण व व्यस्त रेल मार्ग है। इसकी कुल लंबाई 206 किलोमीटर है, जिसे 2100 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत रायगढ़ से झारसुगुड़ा सेक्शन में कोतरलिया रेलवे स्टेशन को चौथी लाइन से जोड़ने का कार्य 11 से 23 अप्रैल तक किया जाएगा। इस कार्य के कारण कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित होगा और कार्य के पूर्ण होने के बाद गाड़ियों के परिचालन में गतिशीलता आएगी।इसमें मुख्य रूप से 11 अप्रैल से 5 मई तक 68861/68862 गोंदिया-झारसुगुड़ा और झारसुगुड़ा-गोंदिया मेमू पैसेंजर स्पेशल बिलासपुर से झारसुगुड़ा के बीच, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22 अप्रैल को 12410 निजामुद्दीन-रायगढ़ गोंड़वाना एक्सप्रेस बिलासपुर से रायगढ़ के बीच और 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23 व 24 अप्रैल को 12409 रायगढ़-निजामुद्दीन गोंडवाना एक्सप्रेस रायगढ़ से बिलासपुर के बीच रद्द की जाएगी।

पिता ने 4 बेटियों को 50 हजार में बेचा, दलाल ने देह व्यापार में धकेला. बिहार से छुड़ाई गई छत्तीसगढ़ की बहनों की आपबीती

दैनिक लोकशक्ति,रायपुर । बिहार के रोहतास जिले से रेस्क्यू कर छत्तीसगढ़ लाई गई 41 लड़कियों में से रायपुर जिले की रहने वाली चार नाबालिग सगी बहनों को उनके पिता ने 50 हजार रुपये में दलाल को बेच दिया था।इसका राजफाश रायपुर की चार बहनों ने पुलिस व महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों को दिए गए बयान में किया है।

पीड़ित नाबालिग ने बताया कि रोहतास जिले के नटवार बाजार की नौटंकी में डांस का काम दिलाने के नाम पर दलाल यहां से लेकर गया था। कुछ दिनों बाद ही सभी को देह व्यापार में धकेल दिया। गंदा काम करने से मना करने पर वह लड़कियों की पिटाई भी करता था। दलाल व उसके गुर्गे सभी लड़कियों को एक झोपड़ीनुमा घर में बंधक बनाकर रखते थे।

रायपुर में सड़क किनारे रहता था परिवार

रेस्क्यू में शामिल अफसरों के मुताबिक, पिछले हफ्ते रोहतास के नटवार बाजार क्षेत्र में पुलिस ने दबिश देकर बंधक बनाकर रखी गई 41 लड़कियों को छुड़ाया। पूछताछ के दौरान रायपुर की चार सगी नाबालिग बहनों में से एक ने बताया कि रायपुर की एक सड़क के

किनारे उसका परिवार रहता है।

कुल पांच बहनें और एक भाई हैं। चार साल पहले मां की मौत के बाद पिता ने सभी को अकेले छोड़ दिया था। तीन साल पहले पिता एक व्यक्ति को लेकर उसके पास आए और कहा कि ये नौटंकी और डांस प्रोग्राम करवाते हैं।इनके यहां पर नाचने का काम है। चारों बहनों को इनके यहां काम मिल जाएगा। इसके बाद सबसे छोटी बहन और छोटा भाई अच्छे तरीके से रह सकेंगे। पिता में लालच में आकर बेटियों का सौदा कर दिया।

डांस के साथ देह व्यापार करने बनाते थे दबाव : रोहतास में चारों बहनों को डांस सिखाया गया। तीन महीने के भीतर चारों स्टेज में नाचने लगीं। इसी बीच उसके मैनेजर ने उससे एक व्यक्ति के साथ सोने के लिए बोला। मना करने पर मारपीट की गई।दलाल ने बोला कि तुम्हारे पिता ने ही बेचा है, इसलिए हमारी हर बात माननी ही पड़ेगी। अन्य लड़कियों के साथ भी ऐसा ही होता था। जो लड़कियां अच्छी नहीं दिखती थी, उन्हें रेस्टोरेंट और होटल में वेटर बना दिया जाता था।

लड़कियों की सैलरी ठेकेदार रखता था। वह कुछ पैसा देता और बाकी अपने पास रख लेता था। लड़कियों को बस्ती से अकेले जाने की इजाजत नहीं थी। ठेकेदार के लोग लड़कियों को अपने साथ ले जाते थे और वापस लाते थे।

पिता और दलाल की तलाश में जुटी पुलिस : नाबालिगों को रेस्क्यू करके रायपुर लाने वाले अफसरों के मुताबिक नाबालिगों के बयान के आधार पर उसके पिता और दलाल की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। आरोपियों के खिलाफनियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।नटवार पुलिस ने नटवार बाजार में दो डांसर ग्रुपों के ठिकाने पर छापेमारी की थी। दोनों ठिकानों से छत्तीसगढ़ से आई 41 नाबालिग लड़कियों को बरामद किया गया। इनके साथ चार लड़कों को भी बरामद किया गया।

सुकमा के ग्रामीणों ने पहली बार राजधानी का किया भ्रमण, विधानसभा कार्यवाही देखकर हुए उत्साहित

स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना के तहत शैक्षणिक भ्रमण पर पहुंचे युवाः पहली बार देखा रेलवे स्टेशन, विधानसभा और वनवासी कल्याण आश्रम

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के दूरस्थ गांवों से आए युवाओं के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना के तहत नियद नेल्लानार योजना में शामिल सिलगेर, पूवर्ती, एलमागुंडा, लखापाल, शालातोंग, साकलेर, छोटेकेडवाल, बगडेगुड़ा और बेदरे जैसे गांवों के 119 युवा पहली बार अपने गांव से बाहर निकले और राजधानी रायपुर पहुंचे।इस शैक्षणिक भ्रमण के दौरान युवाओं ने रेलवे स्टेशन, छत्तीसगढ़ विधानसभा और वनवासी कल्याण आश्रम का दौरा किया।

राजधानी आगमन के दौरान युवाओं ने छत्तीसगढ़ विधानसभा का भ्रमण किया और दर्शक दीर्घा में बैठकर सदन की कार्यवाही देखी, जिससे वे बेहद उत्साहित नजर आए। इस अवसर पर उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा से भेंट की। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने युवाओं से चर्चा करते हुए कहा कि युवा चाहें तो अपने गांव में अमन-चैन और विकास की रोशनी फैला सकते हैं।

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने युवाओं से उनके गांव की स्थिति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने युवाओं को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार उनके गांवों में पक्की सड़क, बिजली, शुद्ध पेयजल, राशन, चिकित्सा और आवास जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने युवाओं को सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की और कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में हम सभी मिलकर छत्तीसगढ़ को विकसित और समृद्ध राज्य बनाएंगे।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने नियद नेल्लानार योजना के तहत गांवों के आर्थिक विकास के लिए विशेष रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि इन गांवों के निकट नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए हैं, जिससे माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सके और शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंचे।

यादव समाज का होली मिलन एवं सम्मान समारोह सम्पन्न हुई

रायपुर। छत्तीसगढ़ झेरिया यादव समाज पंजीयन क्रमांक-5066 से संबद्ध महानगर इकाई रायपुर के तत्वाधान में विगत दिन प्रधान कार्यालय यादव सामाजिक भवन महादेव घाट रायपुरा रायपुर में आयोजित होली मिलन समारोह एवं जनप्रतिनिधियों का सम्मान समारोह गरिमामय एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न हुआ महानगर इकाई एवं ग्रामीण की संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में इस वर्ष हुए नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनावों में विजय प्राप्त यादव समाज के समस्त जनप्रतिनिधियों को प्रतीक चिन्ह एवं यादव समाज गमछा देकर सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ झेरिया यादव समाज के राजनीतिक उदय समाज के भविष्य के लिए शुभ संकेत है। सभी विजेता को शुभकामनाएं एवं बधाई दी। सुन्दर लाल यादव शहर अध्यक्ष ने बताया कि समाज की एकता को सशक्त बनाने समाज की आर्थिक उन्नति शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने आदि उद्देश्य की पूर्ति के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतिवर्ष समाज द्वारा आयोजित किया जा रहा है।

लोकशक्ति
www.lokshakti.in

संपादकीय

युद्ध की स्थिति में शांति की संभावना तलाशें

जब सऊदी अरब में अमेरिका और रूस के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडलों के वार्ता हुई थी, तो उस समय रूस ने साफ कहा था कि वह युद्धविराम नहीं, बल्कि शांति का संपूर्ण समझौता चाहता है, जिसमें उसके सुरक्षा हितों की गारंटी हो। अमेरिका ने यूक्रेन को युद्धविराम पर राजी करने के बाद कहा कि 'गेंद अब रूस के पाले में है'। यूरोपीय नेताओं ने भी सऊदी अरब में हुई अमेरिका-यूक्रेन वार्ता के नतीजों का स्वागत करते हुए यही बात दोहराई है। राष्टपति वोलोदीमीर जेलेन्स्की के युद्धविराम पर राजी होने से प्रसन्न डॉनल्ड ट्रंप प्रशासन ने यूक्रेन के लिए सैनिक मदद फिर शुरू कर दी है। बहरहाल, जेलेन्स्की के बदले ताजा रुख से सचमुच लड़ाई रुकने की संभावना कम ही है। इसलिए कि इसके पहले जब सऊदी अरब में ही अमेरिका और रूस के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडलों के वार्ता हुई थी, तो उस समय रूस ने साफ कहा था कि वह युद्धविराम नहीं, बल्कि शांति का संपूर्ण समझौता चाहता है। जिसमें उसके सुरक्षा हितों की गारंटी हो।

राख हो क्या दहकते नहीं।

चल रही है हवा धड़कने नहीं
बुझी राख हो क्या दहकते नहीं।

पंछी कितने मासूम है वफाओं के
आजकल शहरों में चहकते नहीं।

है गुलाबी सा मिलन विरह काला
प्यार के रंग कभी बदलते नहीं।

नाजुकी भी आज सिरे से गायब है
फूल कागज के कभी महकते नहीं।

सुंदर कलियों फूलों का उपवन है
फिर भी परिंदे यहां चहकते नहीं।

न जाने संजीव ये कैसी सदी है
इश्क में रहकर दिल धड़कते नहीं।

संजीव ठाकुर।

QR CODE SCAN कर प्रेमेन्द्र अग्रवाल द्वारा लिखित पुस्तकें पढ़िये ऑनलाईन

PM : 2024 - Vishwa Sarkar Ka Vikalp

Modimaya_ Vaidik_Netritva

Rashtriya Ekta

DLF-Vadra-Bhrasht Tantra

Silent Assassins Jan11,1966

Accursed & Jihadi Neighbour

ट्रम्प के टैरिफसे दुनिया में नया टेरर

ऋतुपर्ण दवे
rituparndave@gmail.com
rituparndave@gmail.com

अमेरिका में इस बार चुनाव के दौरान ही ट्रंप के आक्रामक तेवर बता रहे थे कि वो न केवल नया कुछ करेंगे बल्कि सभी राष्ट्रपतियों से बड़ी लकीर खीचेंगे। 13 जुलाई 2024 को उन्हें मारने की कोशिश के दौरान चली गोली जो कान छूते निकली और पूरे चुनावी रुख को बदल डाला। कहीं मौत और ट्रंप के बीच का सेकेंड्स से भी कम का ये फासला ही सख्त तेवरों की वजह तो नहीं? उनके मुंह से तब निकले फाइट, फाइट, फाइट शब्द अब हकीकत में दुनिया के लिए चुनौती बन रहे हैं। ट्रंप कड़े और बड़े फैसले लेकर सबसे 'फाइट' कर रहे हैं। क्या उनका दूसरा कार्यकाल अमेरिका और दुनिया में नया इतिहास रचेगा? सबसे ज्यादा परेशानी और हैरानी उनकी हालिया टैरिफघोषणाओं से है जो दुनिया में चिंता का सबब है।

आखिर टैरिफहै क्या? जिससे ट्रंप की घोषणा के बाद बड़ा वैश्विक भूचाल आया? यह दूसरे देशों से आयातित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला टैक्स है। जिसका भुगतान आयातक करते हैं। किसी वस्तु पर 10 फीसदी टैरिफका मतलब भारत से अमेरिका पहुंची 5 डॉलर की उस वस्तु पर 0.50 डॉलर का अतिरिक्त टैक्स है। इससे आयातित वस्तु का दाम बढ़ता है और खरीददार सस्ते घरेलू उत्पाद ढूंढ़ने लगते हैं। नतीजन आयात करने वाले देश को अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ाने में सहयोग मिलता है। लेकिन ट्रंप का नजरिया अलग है। वो इसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था बढ़ाने, नौकरियों की रक्षा करने और कर राजस्व बढ़ाने के तौर पर देखते हैं।

दुनिया के अमीरों में शुमार दिग्गज निवेशक वॉरेन बफेट जिनके बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया के शेयर बाजार की चाल को नियंत्रित करते हैं भी ट्रंप के इस कदम से नाखुश हैं। बफेट टैरिफ नीतियों को युद्ध जैसा कदम मानते हैं। महंगाई और उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ने की आशंकाएं जताते हैं। इससे दीर्घकालीन अवधि में आर्थिक प्रभावों पर दुष्प्रभाव तथा आम उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ने की आशंका जताते हैं। बफेट की टिप्पणी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह ट्रंप के चीन, कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफबढ़ाने की घोषणा के बाद आई। इससे ग्लोबल ट्रेड वॉर और बढ़ा जो निवेशकों की गहरी चिंता का सबब है।

टैरिफ पर अमेरिका और चीन आमने-सामने हैं। चीन चेतावनी दे चुका है कि वो इससे निपटने खातिर तैयार है। अमेरिकी दबाव का मुकाबला करेगा। चीनी वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ते ही दुनिया की दो दिग्गज अर्थव्यवस्थाओं के मध्य व्यापार युद्ध के आसार झलकने लगे हैं। चीनी विदेश मंत्री वांग का बयान कि यदि कोई देश केवल अपने हित आगे बढ़ाने लगे तो दुनिया में जंगल का कानून लागू हो सकता है। उन्होंने याद दिलाया कि अमेरिका को फेंटेनाइल महामारी से निपटने में बीजिंग का सहयोग नहीं भूलना चाहिए। क्या वाशिंगटन इस उदारता का बदला अकारण टैरिफबढ़ा ले रहा है? सच है कि चीन लंबे समय से विश्व का कारखाना बना हुआ है। 1970 के आखिर में जैसे ही चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था ?दुनिया के लिए खोली तबसे सस्ते श्रम और बुनियादी ढांचे में सरकारी निवेश के चलते ऊंचाइयां छूता चला गया। शायद ट्रंप को यही चीनी सफलता चुभ रही हो? दुनिया की निगाहें ट्रंप के टैरिफयुद्ध खासकर चीन की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर है कि उसे कितना नुकसान पहुंच सकता है।

दूसरी ओर ट्रंप इस बार अपने व्यापारी मित्रों, सहयोगियों और सलाहकारों से ज्यादा घिरे दिखते हैं। टैरिफ उनके इकोनॉमिक प्लान्स का हिस्सा है। इससे अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार बढ़ेंगे। गौरतलब है कि उनके खास मित्र एलेन मस्क भारत में संभावनाओं को खोज ही रहे थे कि ट्रंप की सत्ता वापसी हुई। माना कि मस्क की टेस्ला कार की कीमत एक करोड़ होगी उस पर भारत में उतना ही टैरिफ लगेगा जिससे यहां कीमत दो करोड़ हो जाएगी। यदि दबाव के चलते कहीं शून्य टैरिफवाली स्थिति बनी तो वही कार एक करोड़ में भारत में मिलेगी। इससे भारतीय कार बाजार को जबरदस्त चुनौती तय है।

यकीनन बात बहुत बिगड़ चुकी है। भारत समझता है कि ट्रंप जब कनाडा, यूरोपीय देशों और चीन को भी नहीं बख्श रहे तो भारतीय हितों व सम्मान की रक्षा खुद करनी होगी। वहीं ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस के पहले संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए ऐतिहासिक भाषण दिया। इसमें भारत का नाम फिर उन देशों के साथ लिया जिन्होंने अपनी ऊंची शुल्क दर से नरम अमेरिकी नीति का फायदा उठाया। अमेरिका आगामी दो अप्रैल से इन देशों पर 'जैसे को तैसा' या 'आंख के बदले आंख' की तर्ज पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा। जो देश जितना टैरिफ अमेरिकी कंपनियों पर लगाएगा, अमेरिका भी उतना ही अपने यहां लगाएगा। इससे भारतीय एक्सपोर्ट महंगा होगा। खाद्य पदार्थ, टेक्सटाइल्स, कपड़े, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल सामग्रियां अमेरिकी बाजार में महंगी होंगी। नतीजन भारतीय उत्पाद वहां अभी जैसे नहीं टिक पाएंगे।

1951 में अमेरिकी संविधान में 22वें संशोधन के बाद कोई भी व्यक्ति दो बार राष्ट्रपति रह सकता है। ट्रंप आखिरी टर्म में वो कर गुजरना चाहते हैं जो इतिहास बने। वहीं उनके व्यापारी मित्र अपने व्यापारिक हितों में लिपटे दिखते हैं। ट्रंप की मंशा को समझना आसान भी नहीं क्योंकि वो खुद नहीं जानते कि अगले पल क्या कर गुजरेंगे?

जिद्दी ट्रंप किसी मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को नहीं मानते। न यही बताते कि पुराने अमेरिकी प्रशासनों ने ऐसे देशों को क्यों ऊंची दर से शुल्क लगाने दिया। वो अड़ी में हैं। हाल ही में व्हाइट हाउस में ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच प्रेस कांफ्रेन्स के दौरान कैमरों पर जो अप्रिय विवाद दिखा उसकी चहुंओर निंदा हुई। शांति की कीमत के बदले ट्रंप की यूक्रेनी खनिज भंडारों पर कब्जे की मांग यकीनन निंदनीय है। ट्रंप की नीयत ही बदनीयत लगती है। कहीं वो दुनिया को नए ट्रेड वार में धकेल उससे भी कमाने का रास्ता तो नहीं खोज रहे?

मोदी–मंत्रों के साथ विकास की ऊँची उड़ान का संकल्प

मध्यप्रदेश सरकार का बजट

रमेश शर्मा

डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में काम कर रही मध्यप्रदेश सरकार का यह बजट बहुआयामी है। इसमें विकसित मध्यप्रदेश की रूपरेखा के साथ प्रधानमंत्री श्रीनरेंद्र मोदी के तीनों मंत्र की झलक है। मोदीजी के ये तीन मंत्र च्विकास के साथ विरासतज्ज च्द्द4इट्ट का सम्मानज्ज और च्लोकल फॉर वोकलज्ज हैं । इस बजट आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के साथ विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के प्रावधान भी हैं। बिना कोई नया कर लगाये 15त्न की वृद्धि इस बजट की सबसे बड़ी विशेषता है। वर्ष 2025-26 केलिये मध्यप्रदेश सरकार का बजट आ गया है। विशेषताओं, व्यापकताओं और नवाचारों से युक्त है। यह बजट बुधवार 12 मार्च को वित्तमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में प्रस्तुत किया। बजट में एक ओर मध्यप्रदेश की साँस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को सहेजा गया है तो दूसरी ओर आधुनिक दुनियाँ की दौड़ में अग्रणी रहने केलिये औद्योगिकरण को गति देने का प्रयास किया गया है। ताकि मध्यप्रदेश भारत के विकसित प्रातों में अग्रणी बन सके। बजट परिवार का हो, या किसी स्वायत्तशासी संस्थान का। अथवा किसी प्रगतिशील राष्ट्र का। उसमें अतीत के अनुभव, आधारभूत आयामों का सशक्तिकरण, आयवृद्धि के उपाय और व्यय का नियमन होना चाहिए। इसके साथ एक गतिमान वातावरण भी होना चाहिए। मध्यप्रदेश सरकार का यह बजट इन आधारभूत आवश्यकताओं के अनुरूप है। यह अनेक विशेषताओं, व्यापकताओं और नवाचारों से युक्त है। बजट में किसी भी पुरानी योजना को बंद नहीं किया गया है । और न कोई नया टैक्स लगाया गया है। किसी पुराने टैक्स में वृद्धि भी नहीं की गई।

विरासत के साथ विकास

किसी भी परिवार, समाज और देश की अपनी विरासत होती है। उसमें विशेषताओं और वर्जनाओं दोनों की झलक होती है। विरासत और इतिहास वर्तमान पीढ़ी को अपनी विकास यात्रा में गतिमान बनाता है। विरासत में अनेक कथानक भी जुड़े होते हैं। इन कथानकों में उन्नति का संदेश और अवनति के प्रति सावधानी भी होती है। मध्यप्रदेश में ऐसे अनेक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और पुरातात्विक स्थल हैं जो गौरवशाली अतीत के प्रसंगों से जुड़े हैं। मध्यप्रदेश सरकार के इस बजट में उन सभी स्थानों के विकास को महत्व दिया गया है। जिससे पर्यटन बढ़ेगा और मध्यप्रदेश की विशिष्ट पहचान संसार के सामने आ सकेगी। इससे एक तीसरा लाभ भी है जो प्रदेश की वर्तमान पीढ़ी में एक विशिष्ट आत्म विश्वास का संचार करेगा। वही पौधा विशाल वृक्ष

बनकर आसमान की ऊँचाइयों को छूता है जिसकी जड़ें गहरी होतीं हैं। यदि जड़ें कमजोर हैं तो वृक्ष पहली बरसाती बाढ़ में ही बह जायेगा। इसलिये जड़ों का गहरा और मजबूत होना जरूरी है। यही सिद्धांत समाज और राष्ट्र के दीर्घजीवन पर भी लागू होता है। इसीलिए प्रधानमंत्री श्रीनरेंद्र मोदी ने विकसित भारत यात्रा को विरासत से जोड़ा है। जिसे मध्यप्रदेश सरकार ने भी अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है। मध्यप्रदेश देश का हृदय प्रात है। यह संसार के प्राचीनतम भूभागों में से एक है। अरावली, सतपुड़ा और विन्ध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं से समृद्ध यह भूभाग तब भी था जब हिमालय नहीं था और यूरोप ने आकार भी नहीं लिया था। यहाँ करोड़ो वर्ष पुराने जीवाश्म और लाखों वर्ष पुराने शैलचित्र मिलते हैं। डायनासोर के जीवाश्म भी मध्यप्रदेश में मिले हैं। डॉ मोहन सरकार के इस बजट में इन सभी विशिष्ट स्थलों को सहेजने का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने संस्कृति पर्यटन और धर्मस्व विभाग में 1610 करोड़ का प्रावधान किया है। इसके अंतर्गत दो जीवाश्म पार्क विकसित करने किये जायेगें इनमें करोडों वर्ष पुराने डायनासोर के जीवाश्म सहित वे सभी च्फॉसिल्सज्ज सहेजे जायेगें जो आज भी पूरे विश्व केलिये कौतुहल हैं। फॉसिल्स पार्क विकसित हो जाने से संसार भर के शोधकर्ता मध्यप्रदेश आयेंगे। इससे प्रदेश की साख पूरे संसार में बढ़ेगी और स्थानीय नागरिकों को रोजगार के परोक्ष अवसर भी मिलेंगे। इसके साथ औकारेश्वर, महाकाल उज्जैन, मैहर जैसे धार्मिक स्थलों को पर्यटन के रूप में विकसित करने के प्रावधान किये गये हैं। बजट में वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिये दो हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस वर्ष प्रयागराज महाकुंभ में श्रृद्धालुओं की संख्या को देखकर मध्यप्रदेश सरकार अभी से सावधान हुई है। बजट में महाकाल लोक की भाँति ओंकारेश्वर महालोक विकसित करने का प्रावधान है। औकारेश्वर आदि शंकराचार्य जी की तपोस्थली भी रही है। यहाँ आचार्य शंकर अद्वैत वेदान्त संस्थान स्थापना के साथ अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदान्त संस्थान की स्थापना की जा रही है। इसके लिये पाँच सौ करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। त्रेतायुग में भगवान श्रीराम अपनी वनयात्रा में मध्यप्रदेश भी आये थे। चित्रकूट से लेकर अमरकंटक तक उनकी यात्रा के चिन्ह हैं। बजट में रामपथ गमन के विकास केलिये तीस करोड़ का प्रावधान किया गया है। वही? महाभारत काल में भगवान श्रीकृष्ण की यात्रा चिन्हों को समेटने केलिये श्रीकृष्ण पाथेय योजना पर दस करोढ़ रुपये का प्रावधान है। इनके अतिरिक्त धार्मिक और सांस्कृतिक अन्य 14 स्मारकों को सहेजने केलिये बजट में 507 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मध्यप्रदेश सरकार इन सभी स्थलों पर अधोसंरचना के विकास के साथ पर्यटन प्रोत्साहन की योजना पर काम कर रही है । इससे दो लाभ होंगे एक तो पर्यटन से स्थानीय नागरिकों को परोक्ष रोजगार मिलेगा और दूसरा मध्यप्रदेश की विरासत संसार के सामने आ सकेगी। इन सभी स्थलों पर धार्मिक ग्रंथों, साहित्य और वैज्ञानिक अनुसंधान एवं अध्ययन केन्द्र भी स्थापित किये। इस मद पर सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

मध्यप्रदेश सरकार के इस बजट में यदि अपनी विरासत सहेजने का प्रावधान किया गया है तो आधुनिक विकास यात्रा केलिये औद्योगिकरण पर भी जोर दिया है । यह पूरा वर्ष उद्योग वर्ष के रूप में मनाया जायेगा। बजट में 39 नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की घोषणा की गई है, उद्योगों केलिये भूमि आवंटन की अवधि 59 दिन से घटाकर 29 दिन कर दिया गया है। निवेश अनुदान के लंबित प्रकरण के निराकरण केलिये बजट प्रावधान भी बढ़ाया है। इन निर्णयों से मध्यप्रदेश के औद्योगीकरण की गति बढ़ेगी। विशेषकर उद्योग वर्ष मनाने की घोषणा से स्थानीय नागरिकों में उद्योग स्थापना के प्रति रुचि जाग्रत होगी। वे अपनी रुचि, प्रतिभा और क्षमता के अनुरुप अपना उद्योग व्यापार स्थापित करने की ओर प्रोत्साहित होंगे। मध्यप्रदेश सरकार की यह नीति आधुनिक दुनियाँ की प्रगति दौड़ में प्रदेश और देश को अग्रणी बनने केलिये महत्वपूर्ण है। आज की दुनियाँ में विकास की दौड़ की बुनियाद औद्योगिकरण है। औद्योगिकरण की मानों एक स्पर्धा चल रही है। इसमें अग्रणी रहने केलिये औद्योगिकरण में नवाचार जरूरी है। इन नवाचारों केलिये ही पहले मध्यप्रदेश में क्षेत्रीय इन्वेस्टर्स समिट और बाद में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन हुये। बजट के इन प्रावधानों से इन नवाचारों को गति मिलेगी। इसीलिए मध्यप्रदेश सरकार ने अपने बजट में च्विरासतों को सहेजने के साथ औद्योगिक विकास के भी प्रावधान किये हैं। विरासत सहेजने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और औद्योगिक योजनाओं से आधुनिक विकास को गति मिलेगी।

लोकल फॉर वोकल के साथ प्रगति की यात्रा

वित्तमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने प्रत्येक जिले के अपने विशिष्ट उत्पाद को प्रोत्साहित करने की घोषणा की है। इसके स्थापित किये जाने वाले लघु कुटीर और मध्यम उद्योगों को भूमि आवंटन, अनुदान और उत्पाद विक्रय को प्रोत्साहित करने की घोषणा भी की है। मध्यप्रदेश सरकार के इस बजट में सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक विरासत को सहेजने के साथ प्राकृतिक विशेषताओं को भी संसार के सामने लाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशेषता होती है इसे उस क्षेत्र के निवासियों के शिल्प कौशल उत्पाद, फसलों एवं फलों की विशिष्ठता से समझा जा सकता है । इस बजट में प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पाद को प्रोत्साहित करने की घोषणा की गई है। उस विशिष्ट उत्पाद से प्रत्येक जिले की विशेष पहचान वैश्विक होगी, वैश्विक मार्केट मिलेगा। मुद्रा के परिचालन से अर्थ व्यवस्था को मजबूत बनाने में सहायता मिलेगी। इसके लिये परिवहन व्यवस्था का सक्षम होना आवश्यक है। बजट में इस मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति केलिये गांव और कस्बों के साथ मँझरे और टोलों को प्रमुख सड़क मार्गों से जोड़ने की घोषणा की गई है। गांव, कस्बों, मँझरे टोलों तक परिवहन सेवाएँ बढ़ने से स्थानीय उत्पाद को बाजार मिलने में सुविधा होगी और निवेशकों में आकर्षण बढ़ेगा। बजट में प्रत्येक जिले के विशेष के उत्पाद को पहचान बनाने की घोषणा की गई है। इतिहास में भारत को च्सोने की चिड़ियाज्ज कहा गया है। भारत की यह समृद्धि स्थानीय उत्पाद की विशिष्टता के आधार पर ही मिली थी। मध्यप्रदेश सरकार के बजट की यह योजना बहुत दूरगामी परिणाम देने वाली है । आरंभ में भले ही जनरुचि जागरण की गति धीमी रहे, क्रियान्वयन भी धीमा हो सकता है लेकिन के मध्यप्रदेश रचना के लिये यह आवश्यक है। इसलिये वित्तमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने अपने बजट भाषण में और बाद में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अपनी प्रतिक्रिया में वर्ष 2047 में मध्यप्रदेश के वित्तीय स्वरूप का भी संकेत दिया । वर्ष 2047 भारत की स्वतंत्रता का शताब्दी वर्ष है। प्रधानमंत्री श्रीनरेंद्र मोदी उस वर्ष तक भारत को विश्व का सबसे सशक्त राष्ट्र बनाने का संकल्प व्यक्त किया है। यह तभी पूरा होगा जब भारत का प्रत्येक प्रदेश विकास की दौड़ में अग्रणी होगा । मध्यप्रदेश सरकार के बजट में प्रत्येक जिले की पहचान उसके विशिष्ट उत्पाद की इस योजना से विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा और च्लोकल फॉर वोकलज्ज सिद्धांत का क्रियान्वयन भी।

बजट में गरीब, महिला, किसान और युवाओं को सशक्त बनाने के प्रावधान

भारत की पहचान उसके कला-कौशल, प्रतिभा और श्रम साधना से रही है। समृद्धि का केन्द्र युवा महिलाएँ और किसान रहे हैं। भारत की महिलाएँ कृषि कार्य और शिल्प कौशल दोनों में बराबरी से सहभागी रहीं हैं। लेकिन मध्यकाल के दमन और शोषण से स्थिति विपरीत हो गई। इससे गरीबी के रूप में नया वर्ग सामने आया। समाज और राष्ट्र की विकास यात्रा में गरीबी सबसे बड़ी बाधक होती है। मध्यप्रदेश सरकार ने अपने बजट में इन दोनों दिशाओं में प्रावधान किये हैं। एक ओर गरीबी उन्मूलन केलिये अपना खजाना खोला है। मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 1.33 करोड़ परिवारों को निशुल्क राशन दिया जा रहा है। और दूसरी ओर युवा, महिला और किसानों के सशक्तिकरण की योजनाओं पर भी फोकस किया है। बजट में पंचायत और ग्रामीण विकास के लिए 19 हजार 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार ने धान खरीदी में किसानों को समर्थन मूल्य पर अनुदान बढ़ाया है। किसानों को अपनी आय बढ़ाने केलिये पशु पालन केलिये प्रोत्साहित किया है । पाँच किलो दुग्ध उत्पादन पर बोनस देने का प्रावधान किया गया है। सरकार की ग्रामीण विकास योजनाओं से एक ओर गांवों की आधारभूत समस्याओं का समाधान होगा वहीं धान खरीदी के अनुदान और पशुपालन को प्रोत्साहित करने से किसान की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। वित्तमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने अत्याचार अधिनियम के लिए 180 करोड़ का प्रावधान, अनुसूचित जाति विकास के लिए 32 करोड़ का प्रावधान, आहार अनुदान योजना में प्रत्येक महिला को 1500 रुपये देने, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 33 लाख परिवार को निशुल्क राशन दिया जा रहा है। मध्यप्रदेश सरकार बीमा समिति का गठन करके अपने सभी नागरिकों जोड़ेगी। आने वाला समय तकनीकि और कौशल विकास का होगा। जो युवा अपनी प्रतिभा को विकसित कर सकेगा वह प्रगति की दौड़ में अग्रणी होगा। भविष्य की इस गति का आकलन करके मध्यप्रदेश सरकार ने अपने बजट में 22 आईटीआई कॉलेज खोलने की घोषणा की है। स्वास्थ्य की चुनौतियों का सामना करने केलिये चिकित्सकों की संख्या बढ़ाना आवश्यक है। इसके लिये बजट में एमबीबीएस की 400 और मेडिकल पीजी की 255 सीटें बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज खोले जायेगे। मध्यप्रदेश सरकार प्रति वर्ष 50 जनजातीय विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए विदेश भेजा जाएगा। युवाओं में शारीरिक और खेल क्षमताओं का विकास हो सके इसके लिये प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक खेल स्टेडियम खोला जायेगा। वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने अपने बजट भाषण के समापन में कहा कि- आंकड़े नहीं, विश्वास लिखा है, हमने अब आकाश लिखा हैज्ज इस पंक्ति में मध्यप्रदेश के विकास और भविष्य की यात्रा संकल्प है। यह बजट कहने केलिये एक वर्ष का आय व्ययक है लेकिन इसमें विकसित प्राँतों में मध्यप्रदेश को अग्रणी बनाने का प्रारूप भी है।

यह निजी विचार है।

कैबिनेट ने संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) को मंजूरी दी

पीआईबी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) को मंजूरी दे दी है।

संशोधित एनपीडीडी केंद्रीय योजना है जिसमें 1000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त परिव्यय से 15 वें वित्त आयोग चक्र (2021-22 से 2025-26) की अवधि के लिए कुल 2790 करोड़ रुपये का बजट हो गया है। यह योजना डेयरी बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और इसके विस्तार पर केंद्रित है जो इस क्षेत्र की निरंतर वृद्धि और उत्पादकता सुनिश्चित करेगा।

संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम दुग्ध खरीद, प्रसंस्करण क्षमता और बेहतर गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण द्वारा डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देगा। इसका उद्देश्य किसानों को बाजारों तक बेहतर पहुंच प्रदान करना, मूल्य संवर्धन द्वारा बेहतर मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करना और आपूर्ति श्रृंखला दक्षता बढ़ाना है। इससे पशु पालक किसानों की आय में बढ़ोत्तरी और ग्रामीण विकास में वृद्धि होगी।

इस योजना में दो प्रमुख घटक शामिल हैं:

घटक ए डेयरी बुनियादी ढ़ांचे में सुधार के लिए समर्पित है। इसमें दूध शीतक संयंत्र, उन्नत दूध परीक्षण प्रयोगशालाएं और प्रमाणन प्रणाली शामिल हैं। यह नई ग्राम डेयरी सहकारी समितियों के गठन में भी सहायक होगा और पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर), विशेष रूप से दूरदराज और पिछड़े क्षेत्रों तथा पहाड़ी क्षेत्रों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में दूध की खरीद और प्रसंस्करण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएगा। साथ ही समर्पित अनुदान सहायता के साथ इसमें दो दूध उत्पादक कंपनियों का गठन किया जाएगा।

घटक बी में ÷सहकारिता द्वारा डेयरी संचालन (डीटीसी)÷ गतिविधियां शामिल है। इसमें हस्ताक्षरित समझौतों के अनुसार जापान सरकार और जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) के सहयोग से डेयरी विकास संचालन जारी रहेंगी। यह घटक नौ राज्यों (आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल) में डेयरी सहकारी समितियों के सतत विकास, उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन बुनियादी ढांचे में सुधार पर केंद्रित है। एनपीडीडी के क्रियान्वयन से व्यापक सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पड़ा है। इससे 18 लाख 74 हजार से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं, 30,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए हैं। इससे प्रतिदिन 100 लाख 95 हज़ार लीटर दूध खरीद क्षमता में बढ़ोत्तरी हुई है। एनपीडीडी बेहतर दूध परीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए अत्याधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने में भी सहायक रहा है। इसके 51,777 से अधिक ग्राम-स्तरीय दूध परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ किया गया है और 123 लाख 33 हज़ार लीटर की संयुक्त क्षमता वाले 5,123 बल्क दुग्ध शीतक स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, 169 प्रयोगशालाओं को फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड (एफ्टीआईआर) मिल्क एनालाइजर के साथ समुन्नत बनाया गया है, और 232 डेयरी संयंत्रों में मिलावट का पता लगाने के लिए उन्नत व्यवस्था स्थापित की गई है। संशोधित एनपीडीडी से पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में 10,000 नई डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना, प्रसंस्करण, साथ ही एनपीडीडी की क्रियान्वियत परियोजनाओं के अतिरिक्त समर्पित अनुदान सहायता के साथ दो दूध उत्पादक कंपनियों (एमपीसी) के गठन से अतिरिक्त 3 लाख बीस हज़ार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे जिससे विशेष रूप से महिलाओं को लाभ होगा जो डेयरी कार्यबल का 70 प्रतिशत हिस्सा हैं।

डेयरी विकास के लिए संशोधित राष्ट्रीय कार्यक्रम द्वितीय श्वेत क्रांति के अनुरूपता के साथ देश के आधुनिक बुनियादी ढांचे को उन्नत बनाएगा और नई तकनीक और गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं सुविधा द्वारा नवगठित सहकारी समितियों के लिए और अधिक सहायक होगा। यह कार्यक्रम ग्रामीण आजीविका बेहतर बनाने, रोजगार उत्पन्न करने और सुदृढ़ अधिक स्थिति अनुकूलित डेयरी उद्योग निर्माण में सहायग होगा, जिससे देश भर के लाखों किसानों और इससे जुड़े लोग लाभान्वित होंगे।

आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम के पहले बैच का उद्घाटन किया

पीआईबी।

कार्यक्रम, सेवा की भावना को मजबूत करने के लिए जवाबदेह, दयालु और नागरिक-केंद्रित कार्यबल को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है कार्यक्रम का उद्देश्य सेवा को बढ़ावा देने से आगे का है, इसका उद्देश्य लोगों को कौशल सम्पन्न और व्यापक दृष्टिकोण का बनाना भी है: सचिव, आयुष मंत्रालय

आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने 18 मार्च, 2025 को राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम, एक पहल जिसका उद्देश्य सार्वजनिक सेवा के प्रति केंद्र सरकार के कर्मचारियों के दृष्टिकोण को बदलना है, के पहले बैच का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम क्षमता निर्माण आयोग द्वारा शुरू किया गया है। राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम शासन के बड़े मिशन, लोगों के जीवन में सार्थक बदलाव लाने की याद दिलाता है। यह कार्यक्रम सेवा की भावना या 'सेवा भाव' को मजबूत करने के लिए बनाया गया है, ताकि एक ऐसा कार्यबल विकसित हो जो अधिक जवाबदेह हो।

इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल ÷सेवा÷ के विचार को बढ़ावा देना ही नहीं है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य व्यक्तियों को कौशल प्रदान करना और उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाना भी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह प्रशिक्षण प्रतिभागियों को उनके विशेषाधिकारों को पहचानने और यह महसूस करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि वे अपने पेशेवर कर्तव्यों और व्यक्तिगत विकास दोनों के माध्यम से दूसरों की भलाई में कैसे योगदान दे सकते हैं।

इसके अलावा, उप महानिदेशक और क्षमता निर्माण इकाई के प्रमुख श्री सत्यजीत पॉल ने सार्वजनिक सेवा के लिए सही दृष्टिकोण अपनाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा करके, कर्मचारी न केवल अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक निभा सकते हैं, बल्कि तनाव को भी कम कर सकते हैं, समय पर सेवा वितरण सुनिश्चित कर सकते हैं, और अंततः अधिक संगठित और शांतिपूर्ण कार्य वातावरण में योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कर्मचारियों को प्रशिक्षण को अपनाने, इसकी शिक्षाओं का अभ्यास करने और उन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि इन सेवाओं का नागरिकों तक सर्वोत्तम तरीके से पहुँच सुनिश्चित हो सके।

प्रशिक्षण सत्रों का नेतृत्व डॉ. सुबोध कुमार (निदेशक) द्वारा किया जा रहा है तथा क्षमता निर्माण आयोग की सुश्री शिप्रा सिंह (कार्यक्रम समन्वयक) द्वारा संचालित किया जा रहा है। सत्रों में उपस्थित लोगों की सक्रिय भागीदारी देखी गई, जिन्होंने मंत्रालय के भीतर अपनी जिम्मेदारियों तथा सभी हितधारकों के सामूहिक योगदान की गहरी समझ हासिल की।

राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में आयुष मंत्रालय और विभिन्न प्रभागों की भूमिका पर भी चर्चा की गई। प्रतिभागियों ने भारत में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने और नागरिकों के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार लाने में आयुष के योगदान के बारे में जानकारी साझा की।

यह कार्यक्रम संवादात्मक और भागीदारी वाली पद्धति से संचालित है, जो पारंपरिक व्याख्यान-आधारित प्रशिक्षण की जगह संरचित चर्चा, टीमवर्क और समस्या-समाधान अभ्यासों को शामिल करता है। चार छोटे सत्रों की एक श्रृंखला के माध्यम से, कर्मचारियों को अपनी भूमिकाओं पर विचार करने, अपने उद्देश्य को समझने और नागरिक सेवाओं को बढ़ाने पर सक्रिय रूप से संवाद करने का अवसर मिलेगा।

आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाने घर-घर हो रहा सर्वे

संवाददता।

कोरिया जिला प्रशासन द्वारा 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान वय वंदना योजना के तहत कार्ड बनाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है।

कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी के निर्देशानुसार एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रशांत सिंह के मार्गदर्शन में जिला एवं ब्लॉक स्तर की टीमें स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ घर-घर जाकर सर्वे एवं पंजीयन कर रही हैं।

आधार कार्ड एवं राशन कार्ड के आधार पर मिलेगा लाभ इस योजना के तहत 70 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के सभी नागरिक अपने आधार कार्ड और राशन कार्ड के आधार पर आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनवा सकते हैं। इस कार्ड के माध्यम से अस्पताल में भर्ती होने पर 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी। प्रशासन का लक्ष्य है कि जिले के हर पात्र व्यक्ति को इस योजना से जोड़ना है।

आयुष मंत्रालय ने हीटवेव के संबंध में सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए सक्रिय कदम उठाए

पीआईबी। बढ़ते तापमान और भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को जारी की गई सलाह के मद्देनजर, आयुष मंत्रालय ने देश भर में फैले संस्थानों के अपने नेटवर्क के माध्यम से राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया है। इन प्रयासों का उद्देश्य हीटवेव से बचाव के उपायों के बारे में जागरूकता फैलाना है।

आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले संस्थान और संगठन नागरिकों को हीटवेव की रोकथाम के बारे में शिक्षित करने के लिए जागरूकता सत्र, आईईसी सामग्री का वितरण आदि सहित कई गतिविधियां आयोजित कर रहे हैं। यह अभियान नागरिकों को अत्यधिक हीटवेव की स्थिति के दौरान सुरक्षित रहने में मदद करने के लिए वैज्ञानिक प्रमाणों द्वारा समर्थित सुझावों और पारंपरिक कल्याण प्रथाओं पर जोर देता है।

डॉ. एमएम राव, सीएआरआई, भुवनेश्वर

जामनगर स्थित आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (आईटीआरए) ने स्थानीय आबादी को बढ़ते तापमान के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। आईटीआरए ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति अपनी सतत प्रतिबद्धता के तहत 20 मार्च, 2025 को निवासियों को शिक्षित करने और उनकी सुरक्षा करने के लिए एक महत्वपूर्ण गतिविधि आयोजित की-विशेष रूप से उन लोगों को जो गर्मी की महामारी से जुड़े जोखिमों की वजह से इसके बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) में आते हैं। अभियान के दौरान आईटीआरए अस्पताल और आस-पास के क्षेत्र में शैक्षिक पर्चे बांटे गए। ये द्विभाषी पुस्तिकाएं गर्मी से संबंधित बीमारियों को रोकने के लिए बहुत सारा पानी पीना, पीक आवर्स के दौरान सीधी धूप से बचना और गर्मी के तनाव के शुरुआती चेतावनी संकेतों को पहचानना जैसे महत्वपूर्ण सुझाव और व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को वह ज्ञान प्रदान करना है जिसकी उन्हें आवश्यकता है।

डॉ. जयप्रकाश राम ने हीटवेव जागरूकताः ज्ञान, रोकथाम और उपचार पर एक प्रेरक और जानकारीपूर्ण व्याख्यान दिया। आरएआरआई अहमदाबाद में आयोजित इस जीवंत कार्यक्रम ने ओपीडी रोगियों, उनके परिवारों और संस्थान के समर्पित कर्मचारियों को लू (हीटवेव) के खतरों से आत्मविश्वास और देखभाल के साथ निपटने के लिए सामूहिक जागरूकता के लिए एक साथ लाया।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने जीवंत चर्चाओं में भाग लिया और कई लोग पर्चे और भीषण गर्मी से बचने के लिए नए सिरे से दृढ़ संकल्प के साथ घर गए।

केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, झज्जर की डॉ. प्रीति ने योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा की उपचारात्मक शक्तियों के माध्यम से हीटवेव जागरूकता पर मरीजों और कर्मचारियों को मार्गदर्शन दिया।

सांसद ने भोरमदेव मंदिर के विकास हेतु केंद्रीय पर्यटन मंत्री से की मुलाकात, सौंपा पत्र

राजनांदगांव – राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडेय भोरमदेव के विकास के लिए लगातार प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में सांसद संतोष पांडेय ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से सौजन्य भेंट कर छत्तीसगढ़ के खजुराहो भोरमदेव मंदिर के विकास और उसे भव्य-दिव्य स्वरूप देने हेतु राशि आवंटित करने का निवेदन कर पत्र सौंपा। सांसद संतोष पांडेय ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री से भोरमदेव मंदिर के सर्वांगीण विकास के संबंध में विस्तृत चर्चा की। उन्होंने मंत्री को अवगत कराते हुए कहा कि कवर्धा से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर भोरमदेव मंदिर स्थित है। यह दुर्लभ बैगा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र सभी का आंखों का तारा हैं, इसे निहारने के लिए पूरे देश, विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक यहां आते हैं।

जैतापुर परमाणु संयंत्र भारत के 100 गीगावॉट स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य में 10% का योगदान देगाः डॉ. जितेंद्र सिंह

पीआईबी

उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना हरियाणा में गोरखपुर नाम के एक छोटे शहर में स्थापित की जा रही है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने जैतापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए यह खुलासा किया, और इसे भारत के स्वच्छ ऊर्जा भविष्य की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

लोकसभा में उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी नवीनीकरण के अधीन है और पारिस्थितिकी और सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय किए गए हैं।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने जोर देकर कहा कि संरक्षण समूहों की आपत्तियों और भूकंपीय क्षेत्र में इसके स्थान के बारे में चिंताओं के बावजूद सरकार को परियोजना की सुरक्षा पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि समुद्री जीवन और स्थानीय आजीविका के लिए जोखिमों के बारे में बार-बार चिंताएं उठाई गई हैं, और हर बार, सरकार ने ÷इन सभी आशंकाओं को दूर करने की कोशिश की है कि समुद्री जीवन, मत्स्य पालन या आसपास रहने वाले लोगों के लिए ऐसा कोई खतरा नहीं है, यह साबित करने के लिए पर्याप्त संख्या में साक्ष्य-आधारित अध्ययन हैं।÷ उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि प्रक्रियात्मक देरी के कारण दिसंबर 2022 में पर्यावरणीय मंजूरी समाप्त हो गई थी, न कि किसी नए पर्यावरणीय आपत्ति के कारण। उन्होंने समझाया, ÷अगर बहुत गंभीर पर्यावरणीय खतरे या कोई आशंका या सबूत होते, तो हमें पहले भी पर्यावरणीय मंजूरी नहीं मिलती।÷

परियोजना की टाइमलाइन का आकलन देते हुए, मंत्री ने समझाया कि हालांकि प्रारंभिक मंजूरी 2008 में दी गई थी, लेकिन फ्रांसीसी हितधारकों के साथ समझौतों में बदलाव के कारण देरी हुई। अब तकनीकी समझौते अंतिम रूप देने के बाद, फ्रांसीसी पक्ष के साथ वाणिज्यिक शर्तों को तय करने के लिए बातचीत चल रही है। जैतापुर संयंत्र, एक बार चालू होने पर, छह परमाणु रिएक्टरों का समूह होगा, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 1,730 मेगावाट होगी, कुल 10,380 मेगावाट–जो 2047 तक भारत के 100 गीगावॉट परमाणु ऊर्जा लक्ष्य का 10त्न होगा।

परमाणु दायित्व के बारे में चिंताओं को संबोधित करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत का परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व (सीएलएनडी) ढांचा स्पष्ट सुरक्षा उपाय प्रदान करता है। प्राथमिक जिम्मेदारी ऑपरेटर पर है, और 1,500 करोड़ रुपये का एक बीमा पूल स्थापित किया गया है, यदि आवश्यक हो तो सरकार से अतिरिक्त प्रतिबद्धताओं के साथ। इसके अलावा, भारत ने किसी घटना की स्थिति में वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक मुआवजा तंत्र के साथ तालमेल बिठाया है।

एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव में, सरकार विस्तार में तेजी लाने के लिए परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए भी खोल रही है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने हरियाणा में आगामी गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर प्रकाश डाला, जो भारत के पहले उत्तर भारतीय परमाणु परियोजना के रूप में, इस व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है।

केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने शीघ्र राशि स्वीकृत करने का दिया आश्वासन

संवाददाता। । भारतीय कला का एक अज्ञात रत्न छत्तीसगढ़ का खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध भोरमदेव छत्तीसगढ़ के कला तीर्थ के नाम से विख्यात, मैंकल पर्वत श्रृंखला के गोद में बसे 11 वी सदी मे निर्मित भारतीय संस्कृति एवं कला की सम्मोहक छवि के साथ ही साथ धर्म, आध्यात्म, लौकिक जीवन के विविध पक्षों के साथ साथ वन्यजीव अभ्यारण, साल और बीजा के पेंडों की निर्मल छाया को संजोए हुए हैं। मंदिर परिसर में मां काली व हाथ में शिवलिंग रखे हुए हनुमान जी की अद्भुत प्रतिमा विराजित है। साथ ही यहां पुरातत्व विभाग का संग्रहालय स्थित है, जहां खुदाई में निकले हुए विभिन्न प्रकार की मूर्तियां व पुरातत्व अवशेष रखे हुए हैं। इसके अलावा मंदिर क्षेत्र में प्राचीन मड़वा महल व छेरकी महल भी स्थित है।

उक्त पर्यटन स्थल पर सावन माह, महाशिवरात्रि व चैत्र कृष्ण तेरस के पर्व पर मंदिर परिसर पर अत्यधिक श्रद्धालु भगवान के दर्शन हेतु आते हैं। सावन माह मे बारिश के कारण श्रद्धालु को बरसते पानी के बीच ही दर्शन हेतु कतार मे लगना पड़ता है। देश एवं प्रदेश के लाखों भक्तों की आस्था अनुरूप भोरमदेव मंदिर में शेड निर्माण, मंदिर के रख-रखाव व विशेष मरम्मत कार्य सहित प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, लैंडस्कैपिंग व श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाओं के विस्तार सहित विभिन्न प्रकार के कार्यो की नितांत आवश्यकता है। सांसद पांडेय ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री से छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाने वाला भोरमदेव मंदिर व मंदिर परिसर के विकास हेतु 10 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करने का आग्रह किया। इस पर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने भोरमदेव मंदिर के विकास हेतु शीघ्र राशि स्वीकृत करने का आश्वासन दिया। सांसद पांडेय ने मंत्री को भोरमदेव मंदिर में दर्शन करने हेतु पधारने का निमंत्रण भी दिया। जिस पर मंत्री ने मंदिर दर्शन की इच्छा भी जताई।

रास्ता रोककर शराब पीने के लिये पैसे की मांग के साथ जान से मारने की धमकी

आरोपी को चाम्पा पुलिस ने किया गिरफ्तार

जांजगीर चांपा/

रास्ता रोककर शराब पीने के लिए पैसे की मांग के साथ गाली गलौच , मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को चांपा पुलिस ने गिरफ्तार किया है । मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी मनोज भगत निवासी बाधिनपुर थाना पारों जिला मुजफ्फरपुर बिहार हा.मु. कोसमंदा रेल्वे फाटक पास केम्प के द्वारा दिनांक 20 मार्च 25 के सुबह 10:00 बजे अपने केम्प से उसके दोस्त निखिल के साथ अपने निवास कोसमंदा बस्ती तरफ जा रहे थे तभी करीबन 10:20 बजे कोसमंदा रेल्वे फाटक के आगे आरोपी प्रेम यादव द्वारा रास्ता रोककर प्रार्थी से शराब पीने के लिये 500रू. पैसा मांगा । उसके द्वारा नहीं है कहने पर अश्लील गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देकर हाथ मुक्का व डंडा से मारपीट किया । उक्त रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध धारा 119 (1),296,126 (2),351 (3),115 (2) ब्नहस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान *आरोपी प्रेम यादव* निवासी वार्ड नं. 17 फंद्राहीपारा कोसमंदा थाना चांपा को उसके सकुनत से पकड़ा, जिसको घटना के संबंध में पूछताछ किया जो घटना घटित करना स्वीकार किये जाने से विधिवत् गिरफ्तार कर आज उसे न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक जय प्रकाश गुप्ता, महिला प्रआर. श्यामा जायसवाल, आर. माखन साहू, मुद्रिका दुबे, खेमचरण राठौर का सराहनीय योगदान रहा।

शादी का झांसा देकर किया दैहिक शोषण आरोपी चढ़ा नवागढ़ पुलिस के हत्थे

जांजगीर चांपा / संवाददाता। शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण के आरोपी नवागढ़ पुलिस की हत्थे चढ़ा है । मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता और आरोपी सहदेव यादव दोनो एक दूसरे से जानते पहचानते थे। इसी बीच आरोपी सहदेव यादव द्वारा शादी करूंगा बोलकर पीड़िता से दैहिक शोषण करता रहा। पीड़िता द्वारा लगातार शादी करने के लिए बोलती रही लेकिन आरोपी द्वारा टाल मटोल करता रहा । उक्त रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध थाना नवागढ़ में अपराध क्रमांक 136/25 धारा 376(2)(ठ)366.a ipc 4,6 पास्को एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा श्री विवेक शुक्ला के निर्देशन में आरोपी सहदेव यादव को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश कश्यप के कुशल मार्गदर्शन में घेराबंदी कर पकड़ा । उसे घटना के संबंध में पूछताछ करने पर पीड़िता को शादी करने का झांसा देकर दैहिक शोषण करना जुर्म स्वीकार किए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक भास्कर शर्मा थाना प्रभारी नवागढ़, प्रधान आरक्षक मथुरा प्रसाद, महिला प्रधान आरक्षक स्वाती गिरोलकर एवं थाना नवागढ़ स्टॉप का सराहनीय योगदान रहा।

ट्रक के पिछले हिस्से में टकराकर बाइक सवार संजय गर्ग की मौके पर ही मौत.....

जांजगीर-चांपा नगर के व्यवसायी संजय गर्ग का सड़क हादसे में मौत हो गई ।वे 19 मार्च को सुबह नैला से बाइक से बिलासपुर जा रहे थे, इस दौरान ग्राम रसेड़ा के समीप बाइक की टक्कर ट्रक के पिछले हिस्से में हो गई। सर पर गंभीर चोट आने से उसकी मौत हो गई । नैला रेलवे स्टेशन के सामने संजय गर्ग की कान्हा मोबाइल एवं किराने की दुकान वर्षों से संचालित है द्य बुधवार की सुबह किसी काम से नैला से बिलासपुर बाइक से रवाना हुए ,वह आरओबी से कुछ दूर पहुंचने ही थे ,कि उनकी बाइक की टक्कर ट्रक के पिछले हिस्से में हो गई, हादसे में उनके सिर पर गंभीर चोट आई, उन्हें इलाज के लिए अपोलो अस्पताल में जाया गया द्यडॉक्टर उनकी जान नहीं बचा सके और उसकी मौत हो गईद्य इस हादसे में दो बच्चों के सर से पिता का साया छिन गयाद्य मृतक का दाह संस्कार गुरुवार को नैला मुक्ति धाम में किया ।

जिले के 5 विकासखण्डों में हुआ ब्लॉक स्तरीय बस्तर पंडुम का आयोजन

जगदलपुर,संवाददाता। जिले के जगदलपुर, बस्तर, तोकापाल, बास्तानार एवं दरभा विकासखण्ड में गुरुवार को ब्लॉक स्तरीय बस्तर पंडुम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अवसर पर जनप्रतिनिधियों एवं समाज प्रमुखों ने कहा कि यह आयोजन बस्तर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और संवर्धित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। बस्तर पंडुम के माध्यम से पारंपरिक नृत्य, लोकगीत, हस्तशिल्प और आदिवासी रीति-रिवाजों को मंच प्रदान किया जा रहा है, जिससे स्थानीय संस्कृति को नई पहचान मिल रही है।

इस उत्सव में विभिन्न जनजातीय समूह अपनी कला और परंपराओं का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे न केवल सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ेगी बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। जिले के इन सभी ब्लॉक में आयोजित उक्त कार्यक्रम में स्थानीय लोक कलाकारों, जनजातीय समुदायों और संस्कृति प्रेमियों का उत्साह देखते ही बना। बस्तर पंडुम न केवल संस्कृति को सहेजने का प्रयास है बल्कि सामाजिक एकता और पारंपरिक मूल्यों को भी सुदृढ़ करने का एक महत्वपूर्ण अवसर भी है। जिले के इन सभी विकासखंड में बस्तर पंडुम के तहत हजारों प्रतिभागियों ने बढ़-चढ़ कर उत्साहपूर्वक भाग लिया। जिले में बस्तर पंडुम का जिला स्तरीय कार्यक्रम 22 एवं 23 मार्च को इंदिरा प्रियदर्शिनी स्टेडियम जगदलपुर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें ब्लॉक स्तर से चयनित प्रतिभागी शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि बस्तर पंडुम 2025 के अन्तर्गत अनेक विधाएं शामिल की गई। जिसमें जनजातीय नृत्यों के तहत गेड़ी, गौर-माड़िया, ककसाड़, मांदरी, हुलकीपाटा, परब सहित लोक गीत श्रृंखला के तहत जनजातीय गीत- चैतपरब, लेजा, जगारगीत, धनकुल, हुलकी पाटा (रीति-रिवाज, तीज त्यौहार, विवाह पद्धति एवं नामकरण संस्कार आदि) जनजातीय नाट्य श्रेणी में भतरा नाट्य जिन्हें लय एवं ताल, संगीत कला, वाद्य यंत्र, वेषभूषा, मौलिकता, लोकधुन, वाद्ययंत्र, पारंपरिकता, अभिनय, विषय-वस्तु, पटकथा, संवाद, कथानक के मानकों के आधार पर मूल्यांकन किया गया। इसके अलावा जनजातीय वाद्य यंत्रों का प्रदर्शन के तहत धनकुल, ढोल, चिटकुल, तोड़ी, अकुम, झाब, मांदर, मृदंग, बिरिया ढोल, सारंगी, गुदुम, मोहरी, सुलुङ, मुंडाबाजा, चिकारा शामिल रहे। जिन्हें संयोजन, पारंगता, प्रकार, प्राचीनता के आधार पर अंक दिए गए। जनजातीय वेशभूषा एवं आभूषण का प्रदर्शन विधा में लुरकी, करधन, सुतिया, पैरी, बाहूंटा, बिछिया. ऐंठी, बन्धा, फुली, धमेल, नांगमोरी, खोचनी, मुंदरी, सुर्रा, सुता, पटा, पुतरी, नकबेसर जैसे आभूषण में एकरूपता, आकर्षकता, श्रृंगार, पौराणिकता को महत्व दिया गया। जनजातीय शिल्प एवं चित्रकला का प्रदर्शन विधा के अंतर्गत घड़वा, माटी कला, काष्ठ, ढोकरा, लौह प्रस्तर, गोदना, भित्तीचित्र, शीशल, कौड़ी शिल्प, बांस की कंघी, गीकी (चटाई), घास के दानों की माला प्रदर्शन प्रस्तुतियां हुई।

पं. जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना : कक्षा 6वीं में प्रवेश चयन परीक्षा 30 मार्च को

परीक्षा केन्द्र को किया गया परिवर्तित

जांजगीर-चांपा,संवाददाता - पं0 जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना अंतर्गत वर्ष 2025-26 में कक्षा 6वीं में प्रवेश परीक्षा हेतु चयन परीक्षा का आयोजन 30 मार्च 2025 (रविवार) को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ठ अंग्रेजी माध्यम विद्यालय क्रमांक 01 जांजगीर में आयोजित किया गया था। सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास ने बताया कि उक्त संस्था को परिवर्तन करते हुए उनके स्थान पर (बी0टी0आई0 चौक) प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) जांजगीर को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। शेष शर्ते यथावत रहेगी। सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जांजगीर-चांपा एवं सक्ती जिले से प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण उपरांत पात्र विद्यार्थियों का प्रवेश पत्र जारी किया गया है। प्रवेश पत्र का वितरण 24 मार्च 2025 से 28 मार्च 2025 तक कार्यालयीन समय में सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जांजगीर-चांपा से किया जाएगा। यदि किसी कारण वश कार्यालय में नहीं आ पाते हैं, तो उनका प्रवेश पत्र परीक्षा 30 मार्च 2025 को 9.00 बजे वितरण किया जायेगा। परीक्षा में विद्यार्थियों को फोटो युक्त पहचान पत्र के साथ परीक्षा में उपस्थिति होना अनिवार्य है।

जिला रोजगार कार्यालय में 24 मार्च 2025 को प्लेसमेंट कैंप का होगा आयोजन

जांजगीर-चांपा संवाददाता। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र जांजगीर-चांपा द्वारा युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से 24 मार्च 2025 दिन सोमवार को प्रातः 11 बजे 3 बजे तक जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, जांजगीर-चांपा लाईवलीहुड कॉलेज परिसर जॉजगीर में कैंप का आयोजन किया जा रहा है। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि शिविर में टैंगो सिक्युरिटी सर्विसेस प्रा.लि. रायपुर द्वारा सुरक्षा गार्ड के 60 एवं सुरक्षा सुपरवाईजर के 05 पदों पर भर्ती की कार्यवाही की जाएगी। सुरक्षा गार्ड के लिए 10वीं एवं सुरक्षा सुपरवाईजर के लिए 12वीं शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। चयनित उम्मीदवारों का कार्यक्षेत्र रायगढ़ एवं खरसिया रहेगा। सुरक्षा गार्ड के लिए वेतनमान 14500 रुपए से 18000 रुपए एवं सुरक्षा सुपरवाईजर के लिए 18000 रुपए से 20000 रुपए निर्धारित की गई है। प्लेसमेंट कैंप में भाग लेने वाले इच्छुक आवेदक अपने मूल प्रमाण पत्रों के साथ स्वयं उपस्थित होकर कैंप में भाग ले सकते है।

मुड़ापार बायपास में नाली व पुलिया बनाने की मांग

कोरबा, नगर पालिक निगम के वार्ड क्रमांक 29 मुड़ापार के पार्षद गोपाल कुर्रे ने आयुक्त आशुतोष पांडे को पत्र लिखकर मुड़ापार डायवर्सन रोड (बायपास) में सीडीपी योजना अंतर्गत नाली एवं पुलिया निर्माण कराए जाने की मांग रखी है। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि वार्ड क्रमांक 29 मुड़ापार डायवर्सन रोड में जायसवाल पेट्रोल पंप से रामनगर मोड़ तक बड़ी नाली का निर्माण कार्य तथा लकड़ी टाल के सामने कलवर्ट पुलिया का निर्माण किया जाना आवश्यक है क्योंकि बरसात के समय निचली बस्तियों के घरों में पानी का भराव हो जाता है। अगर नाली व पुलिया निर्माण हो जाता है तो समस्या का समाधान हो जाएगा। अतरू मांग है कि सीडीपी के अंतर्गत उपरोक्त कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कराने हेतु शीघ्रातिशीघ्र कदम उठाई जाए। इस कार्य को पूर्ण कराने में लगभग 40 लाख रुपए की अनुमानित राशि की आवश्यकता पड़ सकती है।

खुडमुडी में भगवान श्री सहस्त्रबाहु अर्जुन एवं माता बहादुर कलारिन प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा स्थापना 23 मार्च को

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला महिला अध्यक्ष कलार समाज निर्मला जितेंद्र सिन्हा होंग

राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ कलार समाज ग्राम खुडमुडी जिला राजनांदगांव में भगवान श्री सहस्त्रबाहु अर्जुन एवं माता बहादुर कलारिन प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति स्थापना 23 मार्च को की जा रही है। कार्यक्रम के तहत 23 मार्च को प्रातः 9 बजे माता बहादुर कलारिन प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा एवं पूजा, 11बजे अतिथि स्वागत वंदन अभिनंदन, दोपहर 1 बजे समाज के प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं एवं युवाओं को गौरवशाली सम्मान और संध्या 3 बजे जय बजरंग मानस परिवार जनकपुर खिलौरा वालों का मानस गान होगा। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डागेश्वर सिन्हा प्रांता युवा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ कलार समाज, शिव शंकर डडसेना जिला अध्यक्ष कलार समाज राजनांदगांव,श्रीमती निर्मला जितेंद्र सिन्हा जिला महिला अध्यक्ष कलार समाज राजनांदगांव के मुख्य अतिथि में होगा। बिदेशी राम सिन्हा ग्राम प्रमुख, पवन कुमार सिन्हा युवा मंच, पदमनी सिन्हा महिला मंच एवं समस्त डडसेना सिन्हा कलार समाज ग्राम खुडमुडी नारायण,देवनाथ, मेघनाथ, उभे सिन्हा, प्रेमलाल,खोम लाल,चैतराम, टिकेश्वर, सोहन,इंद्र कुमार, रामहू, बिदेशी,गणेशु, बैन लाल नरोत्तम,राजेश, गोपाल, भुवन,बसंत, भोज सिन्हा, मनोज, रामनाथ, मनीष, हेमंत कुमार,मनहरण, जोहन, कमलेश,गजाधर, नरबदिया बाई सहित आयोजक समिति द्वारा कार्यक्रम की व्यापक तैयारियां कर रही है।

188 न्यायधीशों का ट्रांसफर, हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश..

संवाददाता।

.बिलासपुर बिलासपुर हाई कोर्ट ने बड़े पैमाने पर न्यायधीशों का ट्रांसफर किया है। आठ अलग-अलग आदेश जारी कर 188 जजों को इधर से उधर कर दिया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश से लेकर सिविल जज जूनियर डिवीजन तक कुल 188 जजों के नाम तबादला सूची में शामिल हैं।

चार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , चार सीजेएम रैंक के जज, 60 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के तबादले हुए हैं। 33 सीनियर सिविल जजों के भी तबादला आदेश जारी किए गए है। 87 सिविल जज जूनियर डिवीजन के नाम हैं।

सूरजपुर के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोविंद नारायण जांगड़े को बस्तर (जगदलपुर) का प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाया गया है। किरण चतुर्वेदी प्रीसाइडिंग अफसर छत्तीसगढ़ स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल रायपुर को कोंडागांव जिले का प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाया गया है। राजनांदगांव के फैमिली कोर्ट की जज विनीता वार्नर को सूरजपुर का प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाया गया है। दुर्ग के फैमिली कोर्ट की प्रधान न्यायाधीश गिरिजा देवी मरावी को मुंगेली का प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाया गया है। जगदलपुर के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार ठाकुर को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार विजिलेंस बनाया गया है।

निर्माण कार्यों को गुणवत्तापूर्ण एवं निर्धारित समय-सीमा में करे पूर्ण : कलेक्टर अग्रवाल

गरियाबंद संवाददाता। कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में निर्माण विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, गृह निर्माण मंडल, राष्ट्रीय राजमार्ग, सीजीएमएससी एवं सेतु निगम के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों की गहन समीक्षा की।

कलेक्टर अग्रवाल ने जिले में चल रहे निर्माण कार्यों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि स्वीकृत निर्माण कार्य जनसामान्य की बहुप्रतीक्षित मांगों से संबंधित होते हैं, इन निर्माण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करना चाहिए। जिससे इसका लाभ संबंधित क्षेत्रवासियों को समय में मिल सके। उन्होंने मैदानी ईलाकों सहित वनांचल क्षेत्रों में स्वीकृत एवं प्रगतिरत कार्यो की जानकारी ली। कलेक्टर ने सड़क पुल-पुलिया, शासकीय भवन, न्यायिक भवन एवं स्कूल आदि कार्यो की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने प्रगतिरत कार्यों में तेजी लाते हुए अधिकतम कार्यो को बरसात के मौसम के पहले पूर्ण करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने जिले में पीएम जनमन योजना के तहत चल रहे सड़क निर्माण कार्यो की भी जानकारी ली। उन्होंने ग्रामीणों की सुविधा के लिए सभी कार्यो को उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिये। इस दौरान बैठक में अपर कलेक्टर अरविन्द पाण्डेय सहित संबंधित विभाग के अधिकारीगण मौजूद रहे।

कलेक्टर ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि विकास कार्यों की सूची बनाएं और उसके आधार पर मॉनिटरिंग करें, इससे निर्माण कार्य में तेजी आएगी। उन्होंने विकासखण्डवार चल रहे विकास कार्यो के लिए डायरी संधारित करने और छोटे-बड़े सभी प्रकार के विकास कार्यो को पूर्ण करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने कहा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने निर्माण कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण एजेंसी को निर्माण कार्यों में कोई परेशानी आती है उसकी जानकारी साझा करें। उन्होंने कहा कि विभागीय योजनाओं के अंतर्गत जो भी निर्माण कार्य स्वीकृत किये गए है, उसे शीघ्र प्रारंभ करें और जो कार्य निर्माणाधीन है उसे पूर्ण करें। कलेक्टर ने स्वीकृत निर्माण कार्यों में प्रगतिरत कार्य, अप्रारंभ कार्य के आधार पर अधिकारियों से चर्चा कर सभी कार्यो को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्कूल जतन योजना के अंतर्गत स्कूलों के जीर्णोद्धार कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़क मरम्मत के कार्यों की भी जानकारी लेकर समय में पूर्ण करने के निर्देश दिये।

कार्यालय के पास से कबाड़ की हुई चोरी

कोरबा एसईसीएल दीपका खदान के समानता कार्यालय के पास रखे कबाड़ की चोरी हो गई है। सहायक सुरक्षा उप निरीक्षक ने इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले में चोरी का केस दर्ज किया है।

एसईसीएल दीपका खदान में पदस्थ सहायक सुरक्षा उप निरीक्षक ने बताया कि रविवार-सोमवार की दरमियानी रात खदान के समानता कार्यालय के पास पुराना रोलर और लोहा के स्क्रेप पाइप सहित अन्य लोहे रखे गए थे। सुरक्षा कर्मी की नजर इस स्क्रेप पर पड़ी तो पांच क्विंटल स्क्रेप नहीं थे। एसईसीएल की कोयला खदानों से कबाड़ और डीजल की चोरी को रोकने को लेकर प्रयास जारी है।

मैनुअल पद्धति से जोनल निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक – 32 (प्रथम दौर)

कमांक / 01 /व.ले.लि. / नि.प्र. / ग्रा.यां.सेवा / 2025–26 कोण्डागांव, दिनांक 18 / 03 / 2025

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत 'डी' एवं उच्च श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु मैनुअल जोनल निविदा आमंत्रित की जाती है सभी कार्यों की जोनल निविदा प्रपत्र कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि 03.04.2025 शाम 5.00 बजे तक।

क्र.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रूपये लाख में)
1	2	3
1	रू. 25.00 लाख से कम लागत के विभिन्न निर्माण भवन/मंच/पुलिया/ बाउंड्रीवाल/नाली/सड़क एवं अन्य प्रकार के निर्माण कार्य – वि.ख. माकड़ी	50.00

उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। साथ ही यह जानकारी विभागीय वेबसाइट http://rcs.cg.gov.in दिनांक 24.03.2025 से देखी एवं डाऊनलोड की जा सकती है।

G-242506030/3

कार्यपालन अभियंता,
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
संभाग–कोण्डागांव

खास खबर

184 सहायक प्रबंधक पदोन्नत हो बनेंगे उप प्रबंधक

कोरबा सार्वजनिक क्षेत्र के वृहद उपक्रम कोल् इंडिया के अधीन संचालित अनुषंगी कंपनियो में कार्यरत अधीकारियों को पदोन्नति देते हुए पदोन्नति सूची जारी की गई है। इनमें सहायक प्रबंधक से उप प्रबंधक के पद पर पदोन्नत हुए 184 अधिकारियों की सूची जारी हुई है। ई3 ग्रेड में शामिल रहे सहायक प्रबंधकों को 70,000/- से 2,00,000/- के वेतनमान में ई4 ग्रेड में उप प्रबंधक के पद पर पदोन्नत किया गया है। 17 मार्च को जारी यह आदेश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में लंबित ˘ संख्या 1224-2022 हितेश कुमार साहू बनाम सीआईएल एवं अन्य के परिणाम के अधीन है।

कार्यालयीन आदेश में यह भी कहा गया है कि पदोन्नति होने पर, पदोन्नत कार्यपालक प्रथम बार एक वर्ष की अवधि या सेवानिवृत्ति की तिथि, जो भी पहले हो, के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे। यह पदोन्नति उस तिथि से प्रभावी होगी, जिस दिन उपरोक्त कार्यपालक संबंधित सहायक कंपनियों के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक द्वारा आगे के कार्यभार के लिए तय किए गए पदस्थापन स्थान पर उच्च पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे। यह भी आदेशित किया गया है कि पदोन्नत सभी अधिकारियों को आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा पदोन्नति आदेश रद्द किया जा सकेगा।

डीएलसीसी व डीएलआरसी की बैठक 21 को

कोरबा मार्गदर्शी बैंक योजना अंतर्गत जिला स्तरीय सलाहकार समिति, जिला पुनरीक्षा समिति की बैठक 21 मार्च 2025 को आयोजित की जाएगी।

यह बैठक मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री दिनेष कुमार नाग की अध्यक्षता में शाम 04 बजे जिला पंचायत कोरबा के सभा कक्ष में आयोजित की जाएगी। प्रबंधक मार्गदर्शी बैंक कोरबा ने बताया कि बैठक में विभिन्न शासकीय योजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष की उपलब्धि पर चर्चा, पीएमईजीपी और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना पर चर्चा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जन-धन योजना,एवं पशुपालकों, मत्स्य पालकों एवं उद्यानिकी हेतु किसान क्रेडिट कार्ड पर भी चर्चा की जाएगी।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर कलेक्ट्रेट में कार्यशाला हुई आयोजित

कोरबा कलेक्ट्रेट के सभागार में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिला स्तर के जनसूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारियों सहित विभागीय अधिकारी, कर्मचारी शामिल हुए। कार्यशाला में राज्य सूचना आयोग के अनुभाग अधिकारी श्री ए के वर्मा ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से सूचना के अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी। वर्मा ने बताया कि राज्य सूचना आयोग ने 2022 में एक वेबपोर्टल लॉन्च किया, जिसके माध्यम से अधिकारी और कर्मचारी अपनी जानकारी ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।

विभागीय जाँच वाले प्रकरणों पर जाँच रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें अधिकारी

आयुष्मान, वयवंदन,पीएम आवास, किसान पंजीयन के कार्यों में प्रगति लाने के दिये निर्देश

0 विभागों से डीएमएफअन्तर्गत मंगाए गए प्रस्ताव

0 अंत्यावसायी अंतर्गत ऋण प्राप्त कर नहीं चुकाने वाले हितग्राहियों से राशि वसूली के दिए निर्देश

0 समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने लम्बित प्रकरणों को शीघ्र निराकरण के दिये निर्देश

कोरबा संवाददाता।

कलेक्टर अजीत वसंत ने समय सीमा की बैठक लेकर विभागीय कामकाजों की समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री जनदर्शन, प्रधानमंत्री पोर्टल और राज्यपाल सहित अन्य मंत्रियों से प्रेषित प्रकरणों का समय सीमा के भीतर जाँच कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने विभिन्न विभागों में लंबित विभागीय जाँच के प्रकरणों में शीघ्र जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने एसडीएम को पटवारियों के जाँच प्रतिवेदन तथा जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि लंबे समय से अनुपस्थित शिक्षकों पर की जा रही कार्यवाही के संबंध में जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा की बैठक में कलेक्टर श्री वसंत ने विभागवार लम्बित टीएल के प्रकरणों की समीक्षा की और पुराने लम्बित प्रकरणों पर जाँच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि कलेक्टर जनदर्शन के लंबित प्रकरणों पर भी शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करें। बैठक में कलेक्टर ने अटल मॉनिटरिंग डैशबोर्ड अंतर्गत आयुष्मान, कृषि विभाग, पीएम आवास,महतारी वंदन योजना सहित महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रगति लाते हुए संपूर्ण जानकारी डैशबोर्ड के अनुसार ऑनलाइन फॉर्मेट में अपडेट रखे। उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनाने के कार्य में प्रगति लाने और मृत व्यक्तियों के नाम को लिस्ट से डिलीट करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने व्यवन्दन योजना की समीक्षा कर्तव्य हुए ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना से वंचित पात्र हितग्राहियों को जोड़ने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर श्री वसंत ने अनुभागवार स्कूली विद्यार्थियों के जाति प्रमाणपत्र बनाने के कार्य की समीक्षा करते हुए एसडीएम को छूटे हुए विद्यार्थियों के प्रमाणपत्र बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी एसडीएम और तहसीलदारों को नक्शा सुधार के प्रतिवेदन समय पर प्रेषित करने निर्देशित किया। कलेक्टर ने विद्युत विभाग को निर्देशित किया कि जिले के दूरस्थ और विद्युतविहीन वाले छोटे बसाहटों, पारा,मुहल्लों में बिजली पहुंचाने की दिशा में प्राथमिकता से कार्य करते हुए प्रस्ताव तैयार करें। उन्होंने सभी विभागों को जनहित से जुड़े कार्य और मानवसंसाधन की आवश्यकताओं को ध्यान रखकर दो दिन के भीतर डीएमएफ अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने कॉलेज में निर्माणाधीन गर्ल्स हॉस्टल के कार्य को शीघ्र पूर्ण करने और नए सत्र से हैंडओवर करने के निर्देश दिए। उन्होंने सखी वन स्टॉप सेंटर,दिव्यांग प्रमाण पत्र प्रदान करने लगाए गए शिविर और प्रमाणपत्र वितरण की समीक्षा की। कलेक्टर ने स्वामित्व योजना अंतर्गत अधिकार अभिलेख को अद्यतन करने, एसडीएम और तहसीलदारों को अपने क्षेत्र में सड़क,पेयजल,पहुँचमार्ग सहित अन्य बुनियादी आवश्यकताओं को ध्यान में लाने और संबंधित विभाग से समन्वय कर डीएमएफ अंतर्गत प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री वसंत ने अंत्यावसायी विभाग अंतर्गत स्वरोजगार के लिए ऋण लेकर समय पर राशि जमा नहीं करने वाले हितग्राहियों से राशि वसूली करने के निर्देश तहसीलदारों को दिए। उन्होंने बैठक में ईआफिस संचालन के संबंध में निर्देश देते हुए सभी अधिकारियों को एक अप्रैल से ईआफिस के अंतर्गत कार्य करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने टीएल अंतर्गत सभी प्रकरणों को आगामी 15 दिवस के भीतर क्लीयर करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में डीएफओ कटघोरा श्री निशांत कुमार, निगमायुक्त श्री आशुतोष पांडेय, जिला पंचायत सीईओ श्री दिनेश कुमार नाग,अपर कलेक्टर श्री अनुपम तिवारी, श्री मनोज बंजारे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मेडिकल कॉलेज में 510 बेड की मिलेगी सुविधा

रोजाना करीब 80 से अधिक मरीज इलाज कराने के लिए पहुंच रहे

कोरबा संवाददाता।

कोरबा जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बढ़ती मरीजों की संख्या के साथ सुविधाओं के विस्तार की प्रक्रिया जारी है। आईपीडी में मरीजों की संख्या बढने की वजह से बेड कम पड़ रहे हैं। प्रबंधन को मरीजों के इलाज के लिए ट्रामा सेंटर भवन के हॉल में बेड लगाने पड़ रहे हैं। स्थिति यह होती है कि हॉल भी अब कम पडने लगे हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए अस्पताल परिसर में 50 बेड वाली नए भवन की स्वीकृति दी है। इसका निर्माण कार्य भी चल रहा है। दो से तीन साल के भीतर अस्पताल में 510 बेड से अधिक हो जाएंगे। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीन जिला अस्पताल और ट्रामा सेंटर में मरीजों के इलाज शुरू होने के साथ ही प्रबंधन के पास अब 420 बेड है। अस्पताल में प्रतिदिन लगभग 800 से अधिक ओपीडी (आउट पेंशन डिपार्टमेंट) और आईपीडी (इन पेशेंट डिपार्टमेंट) में रोजाना करीब 80 से अधिक मरीज इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं। इस कारण जिला अस्पताल और ट्रामा सेंटर के भवन के वार्डों के साथ ही हॉल में भी मरीजों के लिए बेड लगाकर इलाज किए जा रहे हैं। जबकि हॉल से अन्य मरीज के साथ परिजनों की आवाजाही होती है। इससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। हालांकि इस समस्या को दूर करने के लिए शासन ने दो नए भवन को स्वीकृति दी है। इसमें शासन ने 50 बेड वाली भवन 16.63 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है।

निर्माण एजेंसी सीजीएमएस को बनाया गया है। ठेका कंपनी ने अस्पताल परिसर के उद्यान की साफ-सफाई के साथ निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि इस भवन निर्माण के कार्य के लिए अभी दो वर्ष का तक समय लग जाएगा। भवन निर्माण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मरीजों को सुविधा का लाभ मिलेगा। यह भवन निर्माण के बाद प्रबंधन को हैंडओवर के बाद अस्पताल में बेड की संख्या 470 बेड हो जाएगी। इसके अलावा 40 बेड वाली आई हॉस्पिटल की भी स्वीकृति मिली है। 50 बेड और 40 बेड अस्पताल का भवन निर्माण पूरा होने के बाद बेड की संख्या 510 बेड हो जाएगी। गौरतलब है कि जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज के अधीन होने के बाद से अस्पताल में सुविधा बढ़ी है। इससे सरकारी अस्पताल में इलाज कराने वाले मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। इसमें सबसे अधिक ग्रामीण, मध्यम वर्गीय व गरीब परिवार के लोग अस्पताल पहुंचते हैं।

चना हितग्राही नवंबर से मार्च तक का अपने दुकानों से चना प्राप्त करें- सिन्हा

कोरबा सामाजिक कार्यकर्ता विनोद सिन्हा ने जारी एक बयान में बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दुकानों में नवंबर माह से चना की आपूर्ति टेंडर के अभाव में बाधित हो गया था जिसमें जनवरी माह में आम उपभोक्ताओं को सूचित किया गया था कि टेंडर के पश्चात बकाया महीना का भी चना वितरण किया जाएगा जिसे छत्तीसगढ़ शासन ने अपना वादा निभाते हुए नवंबर 2024 से मार्च 2025 तक कुल 5 माह का चना फरवरी व मार्च में हितग्राहियों के राशन कार्ड में आवंटित किया गया है।

सिन्हा ने आगे बताया कि माह फरवरी में दो-दो तथा कुछ दुकानों में एक-एक माह का चना वितरण किया गया था जिसको लेकर सिन्हा द्वारा जिला खाद्य अधिकारी से चर्चा की गई थी कि सभी हितग्राहियों को समान रूप से बकाए चने का वितरण सुनिश्चित कराई जाए जिला खाद्य अधिकारी ने सभी राशन कार्ड धारीयो को नवंबर से मार्च तक 5 महीने का चना फरवरी व मार्च में आवंटित की गई है। सिन्हा ने आगे बताया कि कोरबा जिले के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ता राशन कार्ड धारी से निवेदन है कि अपने-अपने क्षेत्र के कोऑपरेटिव दुकानों से चना प्राप्त करें कम चना देने की स्थिति में जिला खाद्य अधिकारी से शिकायत करें ताकि चना सभी को मिलना सुनिश्चित हो सके साथ ही साथ सिन्हा ने सभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दुकानदारों से निवेदन किया है की सभी हितग्राहियों को आवंटित चना वितरण हेतु सुनिश्चित की जाए ताकि गरीबों को परेशानी न हो।

एक सप्ताह में किसान पंजीयन के कार्यों को पूरा करें तहसीलदार

कलेक्टर अजीत वसंत ने समय सीमा की बैठक के पश्चात तहसीलवार लम्बित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने सभी तहसीलदारों को निर्देशित किया कि वे फरवरी माह तक के लंबित प्रकरणों का निराकरण एक अप्रैल से पूर्व करना सुनिश्चित करें।

राज्य के बाहर अध्ययनरत एससी/एसटी, ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी 26 तक कर सकते हैं आवेदन

कोरबा संवाददाता

छत्तीसगढ़ के बाहर अन्य राज्य के शासकीय, अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई एवं डाईट आदि में अध्ययनरत् छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी विद्यार्थियों हेतु शैक्षणिक सत्र 2024-25 अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक (कक्षा 12वीं से उच्चतर) छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों के नवीन एवं नवीनीकरण पंजीयन, संस्थाओं के प्रस्ताव/स्वीकृति लॉक करने के लिए तिथि में वृद्धि की गई है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखने वाले विद्यार्थी 01 फरवरी 2025 से अपना पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण कार्यवाही वेबसाइट पद कर सकते हैं। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरबा से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के बाहर अध्ययनरत् विद्यार्थियों से 19मार्च से 26 मार्च तक नवीन तथा नवीनीकरण के ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, 19मार्च से 28 मार्च तक ड्राफ्ट प्रपोजल लॉक किया जाएगा, साथ ही 30 मार्च 2025 तक सैंक्शन ऑर्डर लॉक करने की तिथि निर्धारित की गई है। निर्धारित तिथियों के पश्चात् शिक्षा सत्र 2024-25 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। साथ ही ड्राफ्ट प्रपोजल लॉक एवं सैंक्शन ऑर्डर लॉक करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जाएगा। उक्त तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं तो इसके लिए संस्था प्रमुख स्वतः जिम्मेदार होंगे।

प्रधानमंत्री जी की यात्रा को यादगार बनाने लोगों में भारी उत्साह: अरूण साव

25 मार्च तक सभी काम पूर्ण करने दिए निर्देश

बिलासपुर (संवाददाता)।

उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री अरूण साव ने मोहभट्ठा में अधिकारियों की बैठक लेकर प्रधानमंत्री जी के 30 मार्च के प्रवास को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अब तक हुए कार्यों की जानकारी लेकर 25 मार्च तक तमाम कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। श्री साव ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का छत्तीसगढ़ और विशेषकर बिलासपुर आगमन हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। उनके कार्यक्रम को लेकर लोगों में बड़ा उत्साह है। इसे ऐतिहासिक एवं यादगार बनाने के लिए लोग ब्रेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के आगमन के पूर्व 25 मार्च से 29 मार्च तक पूरे जिले में विशेष स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश दिए। नव निर्वाचित पार्षद, पंच सरपंच एवं जनप्रतिनिधियों की खास सहभागिता से यह अभियान चलाया जाना चाहिए।

श्री साव ने सभास्थल एवं इसके आस-पास बन रहे पार्किंग स्थल में की जा रही तैयारी का मुआयना किया और अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। अपर मुख्य सचिव एवं जिले के प्रभारी सचिव मनोज कुमार पिंगुआ सहित आईजी संजीव शुक्ला, कलेक्टर अवनीश शरण, एसपी रजनेश सिंह सहित राज्य शासन एवं जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे। उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने कहा कि बिलासपुर को प्रधानमंत्री जी के राज्य स्तरीय कार्यक्रम की मेजबानी का सौभाग्य मिला है। हमे अपनी योजनाओं को अच्छे स्वरूप में पूरे राज्य के लोगों को दिखाने का अच्छा मौका मिल रहा है। पूरे राज्य के लोग इस समारोह में आएंगे।

उन्हें इस कार्यक्रम के जरिए अच्छा संदेश देना है। वे हमारे लिए मेहमान की तरह होंगे। उन्हें पर्याप्त सम्मान देना है। उन्हें परायापन महसूस नहीं होना चाहिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से बिल्हा के आस-पास सहित पूरे जिले की सड़कों की मरम्मत अभियान चलाकर करने के निर्देश दिए। गरमी का मौसम शुरू हो गया है, लोगों को पीने के लिए पर्याप्त पेयजल मिले। बंद पड़े नलकूप तुरंत सुधारा जाये। जल जीवन मिशन के काम की चिंता भी अधिकारी गंभीरता से करें। जल संसाधन विभाग के अधिकारी निस्तारी के लिए जलाशयों से पानी छोड़ने की तैयारी कर लें।

जहां-जहां से मांग आ रही हैं, उसके गेट खोलकर पानी छोड़ें। उन्होंने गांवो और शहरों में 25 मार्च से स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश दिए। नये जनप्रतिनिधियों को इस अभियान का हिस्सा बनाया जाए। उन्होंने विशेषकर अमृत सरोवर और सार्वजनकि स्थलों की साफ-सफाई पर खास जोर दिया। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में संपन्न चुनाव में नये जनप्रतिनिधि चयनित होकर आए हैं। उनके साथ विभिन्न योजनओं के समन्वय से एक उत्सव का माहौल बनाया जाना चाहिए।

प्रभारी सचिव मनोज कुमार पिंगुआ ने वर्तमान में चल रही तैयारियों पर संतोष प्रकट किया। उन्होंने कहा कि मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है। पर्याप्त गरमी पड़ सकती है। इसलिए ठण्डे जल की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाए। सबसे बड़ी बात इसका वितरण सुविधाजनक होने चाहिए। उन्होंने सभी तरह के विपरित हालातों से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। बताया गया कि आयोजन को लेकर रेलवे का महत्वपूर्ण सहयोग मिल रहा है।

बैठक में सभी अधिकारियों ने उन्हें सौंपे गये कार्यो की प्रगति से अवगत कराया। आईजी संजीव शुक्ला ने सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बताया। उन्होंने कि एसपीजी एवं प्रधानमंत्री की प्रोटोकॉल के अनुरूप चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। कलेक्टर अवनीश शरण ने बताया कि सभास्थल पर तैयारियां तेजी से चल रही हैं। लगभग 2 लाख लोगों के समागम की संभावना है। सभास्थल पर 120 सेक्टर बनाकर लोगों के बैठने की व्यवस्था बनाई जा रही है। प्रत्येक सेक्टर में डेढ़ से दो हजार लोग सुविधाजनक तरीके से बैठ पाएंगे।

सेक्टरों में लोगों के सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए 10 अधिकारी कर्मचारी तैनात होंगे। कानून व्यवस्था के लिए 13 राजस्व एवं पुलिस के अधिकारी कर्मचारी भी मोर्चा संभालेंगे। प्रत्येक सेक्टर में साफ-सफाई के साथ मेडिकल कीट के साथ मितानीन एवं ठण्डा पेयजल वितरित किया जायेगा। सभा स्थल के इर्द-गिर्द 8 पार्किंग स्थल बनाये गये हैं। पार्किंक स्थल पर अधिकांश तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं।

प्रत्येक पार्किंग स्थल पर राजस्व एवं पुलिस विभाग के राजपत्रित अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया है। सम्मेलन में आ रहे लोगों को अधिकतम डेढ़ किलोमीटर से ज्यादा पैदल नहीं चलना होगा। पार्किंग स्थल पर एम्बुलैंस, शौचालय, पेयजल व्यवस्था एवं टैंकर्स, एनाउंस सिस्टम, भोजन पण्डाल की समुचित व्यवस्था भी उपलब्ध रहेगी।

शार्ट न्यूज

सूने मकान का ताला टूटा, नकदी सहित लाखों रुपए का जेवर पार

रायपुर। डेयरी बजरंग नगर उरकुरा स्थित सूने मकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोर ने नकदी 2 लाख सहित सोने-चांदी के जेवर पार कर दिए। प्रार्थी की शिकायत पर खमतराई पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। अशोक मिश्रा 53 वर्ष डेयरी बजरंग नगर उरकुरा का रहने वाला है। प्रार्थी ने थाना में शिकायत किया कि अज्ञात चोर ने उसके सूने मकान का ताला तोड़कर आलमारी में रखे नकदी 2 लाख 60 हजार सहित सोने-चांदी के जेवर पार कर दिया। चोरी गए जुमला कीमती करीब साढ़े 3 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। मामले में पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

मुनाफा कमाने का झांसा देकर 7 लाख से अधिक की ठगी

रायपुर । अविवा लाइफ इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड में पैसा लगाने पर अधिक मुनाफा कमाने का झांसा देकर 7 लाख से अधिक की ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। प्रार्थी की शिकायत पर सरस्वती नगर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है। राजकुमार बोथरा 40 वर्ष सेंट्रल एवेंयू चौबे कालोनी का रहने वाला है। प्रार्थी ने थाना में शिकायत किया कि उसके पास अज्ञात मोबाइल नंबर से कॉल आया। उक्त व्यक्ति ने प्रार्थी को अविवा लाइफ इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड में पैसा लगाने पर अधिक मुनाफा कमाने का झांसा देकर 7 लाख 13249 रुपए जमा करवा लिया और पॉलिसी पूरा होने पर रकम वापस ना कर धोखाधड़ी किया। प्रार्थी की शिकायत पर सरस्वती नगर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

ऑफिस से नकदी 95 हजार पार

रायपुर । इंद्रप्रस्थ फेस 1 स्थित ऑफिस का ताला तोड़कर अज्ञात चोर ने नकदी 95 हजार रुपए पार कर दिया। प्रार्थी की शिकायत पर डीडीनगर पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।

मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी नितेश यदू 48 वर्ष एलआईजी टाटीबंध का रहने वाला है। प्रार्थी को इंद्रप्रस्थ कालोनी में ऑफिस चलाता है। बताया जाता है कि अज्ञात चोर ने उसके ऑफिस का ताला तोड़कर आलमारी में रखे नकदी 95 हजार रुपए पार कर दिया। प्रार्थी की शिकायत पर डीडीनगर पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

सुकमा के ग्रामीणों ने पहली बार राजधानी का किया भ्रमण, विधानसभा कार्यवाही देखकर हुए उत्साहित

स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना के तहत शैक्षणिक भ्रमण पर पहुंचे युवाः पहली बार देखा रेलवे स्टेशन, विधानसभा और वनवासी कल्याण आश्रम

रायपुर । छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के दूरस्थ गांवों से आए युवाओं के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना के तहत नियद नेल्लानार योजना में शामिल सिलगेर, पूवर्ती, एलमागुंडा, लखापाल, शालातोंग, साकलेर, छोटेकेडवाल, बगडेगुड़ा और बेदरे जैसे गांवों के 119 युवा पहली बार अपने गांव से बाहर निकले और राजधानी रायपुर पहुंचे।इस शैक्षणिक भ्रमण के दौरान युवाओं ने रेलवे स्टेशन, छत्तीसगढ़ विधानसभा और वनवासी कल्याण आश्रम का दौरा किया।

राजधानी आगमन के दौरान युवाओं ने छत्तीसगढ़ विधानसभा का भ्रमण किया और दर्शक दीर्घा में बैठकर सदन की कार्यवाही देखी, जिससे वे बेहद उत्साहित नजर आए। इस अवसर पर उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा से भेंट की। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने युवाओं से चर्चा करते हुए कहा कि युवा चाहें तो अपने गांव में अमन-चैन और विकास की रोशनी फैला सकते हैं।

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने युवाओं से उनके गांव की स्थिति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने युवाओं को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार उनके गांवों में पक्की सड़क, बिजली, शुद्ध पेयजल, राशन, चिकित्सा और आवास जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने युवाओं को सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की और कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में हम सभी मिलकर छत्तीसगढ़ को विकसित और समृद्ध राज्य बनाएंगे।उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने नियद नेल्लानार योजना के तहत गांवों के आर्थिक विकास के लिए विशेष रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि इन गांवों के निकट नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए हैं, जिससे माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सके और शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंचे। उल्लेखनीय है कि आजादी के 75 साल बाद पहली बार अपने गांव से बाहर निकल कर राजधानी पहुंचे अनेक ग्रामीणों ने प्रदेश की प्रगति को नजदीक से देखा और भविष्य में अपने गांवों के विकास में योगदान देने की इच्छा व्यक्त की। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार यह सुनिश्चित कर रही है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में दूरस्थ क्षेत्रों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचे और वहां के लोग विकास की मुख्यधारा से जुड़ें। राज्य सरकार प्रदेश के माओवाद प्रभावित इलाकों में तेजी से बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ अब इन दूरस्थ गांवों तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे युवाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना और नियद नेल्ला नार योजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे ग्रामीण युवाओं को प्रदेश की विकास प्रक्रिया से जोड़ने में मदद मिल रही है।

सीएम विष्णुदेव साय ने पीएम को सौंपा बस्तर के विकास का रोडमैप

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, विकास कार्यों और नक्सल उन्मूलन पर हुई चर्चा

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 30 मार्च को प्रस्तावित छत्तीसगढ़ दौरे की रूपरेखा साझा की

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाक़ात कर राज्य के विकास संबंधी विस्तृत चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बस्तर विकास के मास्टर प्लान का खाका प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया। इस बैठक में मुख्यमंत्री श्री साय ने बस्तर विकास का मास्टर प्लान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को बुनियादी सुविधाओं, उद्योगों और पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित करने की रूपरेखा शामिल थी। प्रधानमंत्री ने इस योजना पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए राज्य सरकार को हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री को बताया कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। सुरक्षा बलों की संगठित रणनीति एवं जनभागीदारी के चलते नक्सल प्रभावित इलाकों में तेजी से बदलाव आ रहा है। उन्होंने बताया कि पुलिस और केंद्रीय बलों के संयुक्त प्रयासों से कई नक्सल गढ़ों में विकास की किरण पहुंची है, जिससे जनता का विश्वास सरकार की योजनाओं में और मजबूत हुआ है। सरकार का अब पूरा ध्यान बस्तर को नए औद्योगिक और आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करने पर है, जिससे युवाओं को रोजगार और आदिवासी समुदायों को बेहतर जीवन स्तर मिल सके।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्य की नई औद्योगिक नीति और निवेशकों की बढ़ती रुचि पर भी विस्तृत चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने बताया कि निवेश को आसान बनाने के लिए सरकार ने सिंगल विंडो क्लीयरेंस, टैक्स छूट और अनुकूल नीतियों को लागू किया है, जिससे बड़ी कंपनियां छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आकर्षित हो रही हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस मुलाकात में महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को मजबूत किया जा रहा है, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें।

मुख्यमंत्री ने बैठक में बस्तर की ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी प्रधानमंत्री को दी। उन्होंने बताया कि बस्तर के महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से हजारों महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लघु वनोपज, जैविक कृषि, हथकरघा, बांस उद्योग और हस्तशिल्प को प्रोत्साहित कर महिलाओं को न केवल आजीविका के साधन मिल रहे हैं, बल्कि वे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बना रही हैं। इसके अलावा, स्टार्टअप्स और छोटे उद्योगों के माध्यम से बस्तर की महिलाओं को उत्पादन और विपणन से जोड़ने की पहल की जा रही है, जिससे वे आत्मनिर्भर बनकर राज्य की आर्थिक प्रगति में योगदान दे सकें।

प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ दौरा, बड़े विकास कार्यों का होगा शुभारंभ

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 30 मार्च को प्रस्तावित छत्तीसगढ़ दौरे की रूपरेखा साझा की। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री ने इस दौरे को लेकर की जा रही तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की और प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ में चल रही विकास योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया।

जेई भर्ती परीक्षा में बीई डिग्री धारियों को मिले अवसर : विनोद चंद्रकर

महासमुंद। पूर्व संसदीय सचिव छ.ग. शासन व महासमुंद के पूर्व विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने बीई/बीटेक डिग्री धारी अभ्यर्थियों को विभिन्न विभागों में जेई (जूनियर इंजीनियर) भर्ती परीक्षा से वंचित किए जाने की सरकार के अव्यवहारिकता पूर्ण निर्णय की निंदा की है। श्री चंद्राकर ने कहा कि इससे पूर्व सरकार द्वारा बी.एड. डिग्रीधारियों की सेवा समाप्त कर डीएलएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षक भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। जिससे हजारों बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी बेरोजगार हुए हैं। अब पुनः प्रदेश के लगभग 25 हजार से अधिक बीई/बी.टेक डिग्रीधारी अभ्यर्थियों में सरकार एवं प्रशासन के अदूरदर्शिता पूर्ण निर्णय से आक्रोश व्याप्त है। सरकार के इस निर्णय से बीई क्वालीफाईड छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी वर्तमान में सरकार द्वारा पीएचई विभाग में जेई सहित कुल 128 पदों में भर्ती के लिए जेई/बी.टेक डिग्रीधारियों को भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। केवल डिप्लोमाधारी छात्रों को ही परीक्षा के लिए पात्र माना गया है।

श्री चंद्राकर ने कहा कि सरकार के भेदभाव पूर्ण नीति से प्रदेश के बीई/बी.टेक डिग्रीधारी युवाओं में गहरी नाराजगी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं मानने के विरोध में प्रदेश के युवा सरकार के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाने विवश हो रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में जूनियर इंजीनियर भर्ती के लिए निकाली गई वेंकेंसी का परीक्षा व्यापमं द्वारा लिया जाना है। जिसमें सिर्फडिप्लोमाधारी को ही योग्य मानना बीई/ बी.टेक डिग्रीधारी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है। डिप्लोपा के साथ डिग्रीधारियों को भर्ती परीक्षा में शामिल होने बराबर का अवसर मिलना चाहिए। जिससे प्रदेश के युवा सुरक्षित भविष्य को लेकर चिंतामुक्त हो सके। सरकार के भेदभाव पूर्ण नीति से प्रदेश के हजारों युवा बेरोजगारी का दंश झेलने विवश हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के इस तरह अव्यहारिकता पूर्ण निर्णय से भविष्य में बीई/बी.टेक डिग्री करने युवाओं की रूचि घटेगी। जिसका परिणाम स्वरूप इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के अस्तित्व पर संकट उत्पन्न होगा। श्री चंद्राकर ने कहा कि प्रदेश के बीटेक डिग्री वाले अभ्यर्थी काफी समय से मांग कर रहे हैं कि जेई भर्ती के लिए उनकी डिग्री को भी अर्ह माना जाए। जेई भर्ती के लिए केवल डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों को अर्ह माना जाना उनके साथ अन्याय है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश के बीई/बी.टेक डिग्रीधारी युवाओं में उम्मीद जगी थी कि उन्हें भी जेई भर्ती में शामिल होने का अवसर मिलेगा।

जोगीपाली-कनकी जंगल में लगी भीषण आग

कोरबा-रायपुर जिले के जोगीपाली-कनकी जंगल में बीती रात भीषण आग लग गई, जिससे जंगल धधकता रहा। आग धीरे-धीरे विकराल रूप धारण कर बड़े इलाके में फैल गई। ग्राम पंचायत जोगीपाली के ग्रामीणों ने जंगल में आग लगने की सूचना वन विभाग को दी, लेकिन वनकर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश करते नहीं दिखे। आग के कारण जंगल को भारी नुकसान हुआ है।

वन परिक्षेत्र पंडरिया पूर्व अंतर्गत अवैध लकड़ी परिवहन करते लकड़ी सहित वाहन जप्त किया गया

कवर्धा। वनमंडल के पंडरिया पूर्व परिक्षेत्र अंतर्गत वनक्षेत्र कक्ष क्रमांक पी.एफ 515 में अवैध रूप से लकड़ी का परिवहन करते पाये जाने पर लकड़ी सहित प्रयुक्त वाहन को जप्त किया गया। वनमंडलाधिकारी, कवर्धा से प्राप्त जानकारी के अनुसार पंडरिया पूर्व परिक्षेत्र अंतर्गत वनक्षेत्र कक्ष क्रमांक पी.एफ 515 परिसर खैरडोंगरी में अज्ञात व्यक्ति द्वारा ट्रेक्टर से जलाऊ लकड़ी परिवहन करने की सूचना मुखबिर से प्राप्त हुई। इस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए वनमंडलाधिकारी कवर्धा के निर्देश एवं उप वनमंडलाधिकारी पंडरिया के मार्गदर्शन में वन परिक्षेत्र अधिकारी, पंडरिया पूर्व श्री महेन्द्र कुमार जोशी,

परिक्षेत्र सहायक नरसिंहपुर श्री अरूण कुमार दुबे, परिसर रक्षक नरसिंहपुर श्री पूनाराम धुर्वे, परिसर रक्षक खैरडोंगरी श्री श्रीराम गुप्ता, श्री राधेलाल पंद्राम भृत्य, वन सुरक्षा समिति सरैहा के अध्यक्ष तथा सदस्यों की संयुक्त समिति गठित कर दिनांक 17.03.2025 की रात्रि लगभग 11.00 बजे पंडरिया पूर्व परिक्षेत्र अंतर्गत वनक्षेत्र कक्ष क्रमांक पी.एफ 515 परिसर खैरडोंगरी में दबिश दी गयी। मौके पर उनके द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 32, 33(1)'क' धारा 41(3), 42, 52 के अनुसार अभिवन (वनोपज) नियम 2001 नियम 03 के अनुसार अवैध परिवहन में प्रयुक्त अन्य मिश्रित प्रजाति के जलाऊ 02 चट्टा सहित वाहन ट्रेक्टर स्वराज 735 एफ ई ट्राली सहित जप्त किया गया। आरोपी वाहन चालक मुकेश व. रोहित साहू साकिन खैरडोंगरी के विरूद्ध वन अपराध प्रकरण क्रमांक 20815/06 दिनांक 17.03.2025 पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही जारी है।

2024-25 में अप्रैल से फरवरी तक 11,581 करोड़ रुपये का खनिज राजस्व अर्जित

खनिज क्षेत्र में पारदर्शिता और नवाचार का नया अध्यायः खनिज प्रबंधन में डिजिटल युग की नई शुरुआत

बैलाडीला क्षेत्र में तीन नए लौह अयस्क ब्लॉकों की ई-नीलामी प्रक्रिया जारी

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पारदर्शी खनन नीति, ई-नीलामी, डिजिटल निगरानी और पर्यावरण-संवेदनशील खनन रणनीतियों को अपनाकर प्रदेश के आर्थिक और औद्योगिक विकास को नए आयाम दिए है। खनिज संसाधनों के सुव्यवस्थित उत्खनन के चलते बीते वर्षों में छत्तीसगढ़ के खनिज राजस्व में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य के गठन के समय की तुलना में खनिज राजस्व में 30 गुना वृद्धि हुई है, जो 2023-24 में 13,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और 2024-25 में अप्रैल से फरवरी तक ही 11,581 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया जा चुका है। यह पारदर्शी खनन नीति और प्रभावी प्रशासन का परिणाम है। अब तक 44 खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी सफलतापूर्वक की जा चुकी है, जिसमें अब तक चूना पत्थर के 14, लौह अयस्क के 9, बॉक्साइट के 11, स्वर्ण के 3, निकल, क्रोमियम के 2, ग्रेफाइट के 2, ग्लूकोनाइट के 2 और लिथियम के 1 खनिज ब्लाक की निलामी की गई है। प्रदेश में अब तक 10 क्रिटिकल एवं डीप सीटेड मिनरल्स ब्लॉक्स की सफलतापूर्वक नीलामी

भारत सरकार द्वारा देश के आर्थिक एवं सामरिक विकास को ध्यान में रखते हुए क्रिटिकल एवं सामरिक महत्व के खनिजों के लिए राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन की घोषणा जनवरी, 2025 में की गई है। इस के अनुरूप प्रदेश में विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 से ही क्रिटिकल एवं सामरिक महत्व के खनिजों के अन्वेषण / खोज पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसके तहत 56 अन्वेषण परियोजनाओं में से 31 परियोजनाओं अंतर्गत क्रिटिकल एवं डीप सीटेड मिनरल्स पर कार्य किये जा रहे है। प्रदेश में अब तक 10 क्रिटिकल एवं डीप सीटेड मिनरल्स ब्लॉक्स जिसमें लिथियम का 1, स्वर्ण का 3, निकल, क्रोमियम का 2, ग्रेफाइट का 2 ग्लूकोनाइट के 2 मिनरल ब्लॉक की नीलामी की गई है।

देश में पहली बार खनिज लिथियम ब्लॉक की सफलतापूर्वक नीलामी की कार्यवाही भारत सरकार द्वारा की गई है जिसके तहत् जिला कोरबा के कटघोरा लिथियम ब्लॉक को मेसर्स साउथ मायकी मायनिंग कंपनी को 76 प्रतिशत प्रीमियम राशि पर आबंटित किया गया है। राज्य के सुकमा एवं कोरबा जिले में भी लिथियम अन्वेषण कार्य किया जा रहा है जिसमें लिथियम के भण्डार पाये जाने की पूर्ण संभावना है।

बैलाडीला क्षेत्र भारत के सबसे बड़े लौह अयस्क भंडारों में से एक है। यहां तीन नए लौह अयस्क ब्लॉकों की ई-नीलामी प्रक्रिया जारी है, जिसे मार्च 2025 तक पूरा किया जाएगा। इसके अलावा कांकेर जिले के हाहालद्दी लौह अयस्क खनिज ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है।

पर्यावरण संतुलन और पारदर्शी निगरानी प्रणाली

पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखते हुए खनन क्षेत्र को अधिक पारदर्शी और वैज्ञानिक रूप से संचालित करने के लिए सरकार ने कई नई पहल की हैं। सेटेलाइट इमेजरी और माइनिंग सर्विलियेंस सिस्टम के माध्यम से अवैध खनन की निगरानी की जा रही है। गौण खनिज खानों में सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक पद्धति से खनन को बढ़ावा देने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है। राज्य सरकार बेहतर कार्य करने वाले पट्टेधारियों को 'स्टार रेटिंग' प्रणाली के तहत प्रोत्साहित कर रही है। खनिज राजस्व से सामाजिक विकास और बुनियादी सुविधाओं में निवेशखनिज राजस्व का एक बड़ा हिस्सा प्रदेश के सामाजिक विकास में निवेश किया जा रहा है। जिला खनिज संस्थान न्यास के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 1,673 करोड़ रुपये की निधि प्राप्त हुई है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल और कौशल विकास सहित 9,362 विकास कार्यों को मंजूरी दी गई।

सुरक्षा की दृष्टि से 9 एसएलआरएम सेंटर के 405 स्वच्छता दीदियों को स्वच्छता किट वितरित किया गया

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में 9 एस.एल.आर.एम. सेंटर संचालित हो रहे है। जहां पर भिलाई शहर से निकलने वाले गीले एवं सूखे कचरे को अलग-अलग कर सेग्रिगेट किया जाता है। गीले कचरे से खाद बनाया जाता है और सूखे कचरे को छांट कर पुनः उपयोग के लिए स्वच्छता दीदीयों द्वारा बेच दिया जाता है। स्वच्छता दीदीयों को निगम द्वारा जीवन यापन के लिए एक निर्धारित मानदेय राशि भी प्रदान किया जाता है, उसके साथ ही छांट कर बेचे गये सामग्री से मिलने वाली राशि को स्वच्छता दीदीयों द्वारा आपस में बांट लिया जाता है।

आज नगर निगम भिलाई आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय एस.एल.आर.एम. सेंटर जाकर स्वच्छता दीदीयां स्वस्थ रहे इसलिए उन्हे स्वच्छता किट वितरित किया गया। जिसमें प्रमुख रूप से वर्दी (महिलाओ के लिए साड़ी, ब्लाउज, पेटिकोट सहित), मास्क, केनवास शूज, गमबूट, रबर ग्लबस, टोपी, एपरन, मोजा, काटन ग्लबस, रैनकोट, नेम बैज, पहचान पत्र आदि प्रदान किया गया। स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली ने बताया कि समय-समय पर सफाई कर्मचारियो का स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जाता है। स्वच्छता किट प्रदान करने से उन्हे कार्य करने में बहुत सहुलियत होगा। कुछ कर्मचारी ऐसे है, जिन्हे सब पहन कर कार्य करने में अटपटा लगता है निकाल देते है। हम सब लोग उन्हे पहनने के लिए बीच-बीच में टोकते रहते है। स्वच्छता दीदीयों द्वारा सफाई के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है।वर्तमान में 9 एस.एल.आर.एम. सेंटर नेहरू नगर, कोसानगर, खम्हरिया, बटालियन, राधिका नगर, पीली मिटटी, कुरूद, बैकुण्ठधाम, गौतम नगर खुर्सीपार में संचालित हो रहा है। स्वच्छता किट वितरण के दौरान कार्यपालन अभियंता रवि सिन्हा, सहायक अभियंता प्रिया करसे, उपअभियंता चंदन निर्मलकर, जनसम्पर्क अधिकारी अजय शुक्ला, जोन स्वास्थ्य अधिकारी हेमंत मांझी, जोन सहायक राजस्व अधिकारी बालकृष्ण नायडू, पीआईयू अभिनव ठोकने, सुभम पाटनी आदि उपस्थित रहे।

स्वामी,मुद्रक,प्रकाशक प्रेमेन्द्र अग्रवाल द्वारा अस्मा पब्लिशर्स इण्डिया प्राईवेट लि.,जयस्तंभ चौक, रायपुर से मुद्रित कर तथा 5/756 रामसागरपारा, सिंधी स्कूल के पीछे, स्टेशनरी हाऊस, रायपुर 492001 (छ.ग.) से प्रकाशित। **संपादक प्रेमेन्द्र अग्रवाल ।**
www.lokshakti.in, lokshaktidaily@gmail.com, twitter.com/lokshaktidaily, facebook.com/lokshaktidaily **कार्यकारी संपादक : राजेश अग्रवाल** (किसी भी विवाद पर न्यायालय क्षेत्र रायपुर होगा)